कल्पमेधा

हम अपने विवेक की कसौटी पर कस कर ही धर्मग्रंथों तथा धर्मगुरुओं की बातें मानेंगे, तो फिर कोई झगड़ा पैदा नहीं होगा। कोई भी बात धर्म की किताब में लिखी है, इसलिए मत मानो।

– विनोबा भावे

घाटी में आतंक

जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद से दावा किया जाता रहा है कि घाटी में आतंकवादी गतिविधियां कम हो गई हैं। दहशतगर्द केवल कुछ इलाकों तक सिमट गए हैं। मगर थोड़े-थोड़े समय पर जिस तरह आतंकवादी अपनी रणनीति बदल कर कभी सामान्य नागरिकों, तो कभी सुरक्षाबलों के काफिले पर हमला करने में कामयाब हो जा रहे हैं, उसे देखते हुए सरकार के दावे पर यकीन करना मुश्किल होता है। शनिवार रात को भी दो जगहों पर आतंकी हमले हुए। शोपियां में एक स्थानीय भाजपा नेता की गोली मार कर हत्या कर दी गई। पहलगाम में राजस्थान से गए एक पर्यटक दंपति को गोली मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। इसी महीने वायुसेना के एक काफिले पर हमला कर एक सैनिक की हत्या कर दी गई। उसमें पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। करीब महीने भर के भीतर बाहरी लोगों को निशाना बना कर और सैनिक काफिले पर घात लगा कर हमले की कई घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में स्वाभाविक ही पूछा जा रहा है कि आखिर घाटी में आतंकवाद को समाप्त करने के तमाम दावे खोखले क्यों साबित हो रहे हैं। इस तरह कब तक निर्दोष लोग और सैनिक दहशतगर्दों का शिकार बनते रहेंगे।

पिछले नौ-दस वर्षों से कश्मीर घाटी में निरंतर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दहशतगर्दों को मदद पहुंचाने वालों की पहचान कर उनके बैंक खाते बंद किए गए और उन्हें सलाखों के पीछे डाला गया है। सीमा पार से घुसपैठ करने वालों पर चौकस नजर रखी जाती है। सड़क के जरिए पाकिस्तान से होने वाली तिजारत बंद है। नोटबंदी के बाद दावा किया गया था कि इससे आतंकवादी संगठनों तक वित्तीय मदद पहुंचनी बंद हो जाएगी। विशेष राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद लंबे समय तक घाटी में सैन्य सक्रियता बनी रही। खुफिया एजंसियां पहले से काफी चाक-चौबंद हुई हैं। इन सबके बावजूद अगर आतंकी संगठन घाटी में न सिर्फ सक्रिय हैं, बल्कि अपनी साजिशों को अंजाम देने में कामयाब भी हो रहे हैं, तो सरकार की रणनीति और सुरक्षाबलों की तैयारियों पर सवाल उठने स्वाभाविक हैं। उन तक किस तरह वित्तीय मदद और गोली-बारूद, हथियार जैसे साजो-सामान पहुंच पा रहे हैं, कैसे वे सैन्य गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर ले रहे हैं, इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

बीते कुछ वर्षों में चिंता पैदा करने वाले तथ्य भी उजागर होते रहे हैं कि स्थानीय युवाओं में आतंकवाद की तरफ रुझान बढ़ा है। कुछ शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी दफ्तरों में ऐसे लोगों की पहचान की गई, जो कश्मीरी युवाओं को हथियार उठाने के लिए उकसाते थे। दो वर्ष पहले खुद केंद्रीय गृहमंत्रालय ने माना था कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद कश्मीरी युवाओं की आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता बढ़ी है। दहशतगर्द ऐसे स्थानीय लोगों में बंदूक के बल पर दहशत भरने में कामयाब हो रहे हैं, जो सरकारी योजनाओं और रणनीतियों में किसी भी तरह से मदद करते हैं। शोपियां में ऐजाज अहमद नाम के जिस भाजपा नेता की हत्या कर दी गई, वह पहले वहां का सरपंच रह चुका था। इसी तरह, कई कश्मीरी सैनिकों और पुलिस कर्मियों को भी निशाना बना कर मारा जा चुका है। फिर जिस राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार ही पर्यटन है, वहां पर्यटकों पर हमला बुरा असर ही डालेगा। इन घटनाओं से सबक लेते हुए आतंकवाद से निपटने के लिए नई रणनीति बनाने की जरूरत है।

हादसे पर सवाल

हेलिकाप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति सहित कई ताकतवर लोगों की जिस तरह मौत हो गई, उसमें ऐसी घटनाओं को हादसे के अलावा अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव के लिहाज से भी देखा जाने लगता है। गौरतलब है कि रविवार को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, वहां के विदेश मंत्री और कई अन्य अहम लोग एक हेलिकाप्टर पर सवार होकर तबरेज शहर की ओर जा रहे थे। इसी बीच मौसम खराब होने के कारण हेलिकाप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें राष्ट्रपति रईसी सहित वहां के विदेश मंत्री हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन, ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती, चालक और सुरक्षा प्रमुख मारे गए। राष्ट्रपति रईसी रविवार को अजरबैजान में किज कलासी और खोदाफरिन बांध का उद्घाटन करने गए थे। जाहिर है, अपनी सीमा में ईरान के शीर्ष नेता और उनके सहयोगियों को इस बात की आशंका भी न रही होगी कि ऐसा कोई हादसा हो सकता है। भारत सहित कई देशों ने इस घटना पर शोक संवेदना जताई है।

यह बेहद अफसोसनाक है कि पिछले कुछ वर्षों में ईरान की कुछ महत्त्वपूर्ण शख्सियतों की जान या तो हादसे में चली गई या फिर उनकी हत्या कर दी गई। मसलन, ईरान में 2020 में एक नायक की तरह मशहूर कुर्द फोर्स के जनरल कासिम सुलेमानी की मौत में अमेरिकी ड्रोन से हमले के आरोप लगे। फिर उसी वर्ष ईरान के मुख्य परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की भी हत्या कर दी गई। वहां हुए कुछ अन्य आतंकवादी हमलों में अमेरिका या फिर इजराइल का हाथ होने की आशंका जताई गई। हाल में इजराइल और अमेरिका के प्रति ईरान के सख्त रुख के मद्देनजर ताजा हादसे को लेकर भी किसी साजिश की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब तक सामने आए तथ्यों के मुताबिक बेहद खराब मौसम की वजह से हेलिकाप्टर हादसे का शिकार हो गया। मगर कुछ लोगों का सवाल है कि अगर मौसम ही कारण था, तो उसी काफिले में शामिल अन्य दो हेलिकाप्टर सुरक्षित कैसे अपने गंतव्य तक पहुंच गए। इस हादसे की असली वजहें तो व्यापक जांच के बाद सामने आएंगी, लेकिन फिलहाल ईरान के सामने एक नाजुक स्थिति से निपटने की चुनौती है।

निर्यात संबंधी नई रणनीति की जरूरत

भारत ने द्विपक्षीय व्यापार संधियों और समझौतों से छोटी अर्थव्यवस्थाओं के साथ विदेश व्यापार और निर्यात रणनीति को सकारात्मक विकल्प दिए हैं।

जयंतीलाल भंडारी

हाल के वर्षों में विदेश व्यापार तथा निर्यात बढ़ाने में दुनिया के वही देश सफल रहे हैं, जिन्होंने अपनी विदेश व्यापार नीति में उपयुक्त परिवर्तन किए हैं। इन देशों में भारत भी शामिल है। पिछले एक दशक में भारत ने पड़ोसी देशों के साथ कारोबार बढ़ाने के लिए 'पड़ोसी प्रथम' नीति, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों (आसियान) के साथ 'एक्ट ईस्ट' नीति और प्रमुख देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) करने की रणनीति सहित नई 'लाजिस्टिक नीति 2022' और नई विदेश व्यापार नीति 2023 लागू की है। इसके बेहतर परिणाम मिले हैं। भारत के विदेश व्यापार में लगातार वृद्धि के साथ निर्यात की ऊंचाइयां भी बढ़ी हैं। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्तवर्ष 2023-24 में भारत से माल एवं सेवाओं का कुल निर्यात 776.68 अरब डालर रहा, जो वित्तवर्ष 2022-23 में 776.40 अरब डालर था। जहां पिछले वर्ष कुल आयात 854.80 अरब डालर का रहा, वहीं वर्ष 2022-23 में कुल आयात 898 अरब डालर का था। इस तरह पिछले वर्ष आयात में कमी से कुल व्यापार घाटे में 36 फीसद की कमी दर्ज हुई है। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से रियायत पर कच्चे तेल का आयात करना जारी रखा और वित्तवर्ष 2022-23 में करीब पांच अरब डालर और 2023-24 में करीब आठ अरब डालर की बड़ी बचत की।

विदेश व्यापार के मोर्चे पर भारत भारत ने पिछले कई वर्षों से डब्लूटीओ द्वारा प्रभावी भूमिका न निभाए जाने से विश्व व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव को समझते हुए अपने विदेश व्यापार को बढ़ाने के कई अन्य कदम उठाए हैं। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अब भारत पड़ोसी देशों- बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान के साथ विदेश व्यापार को बढ़ाने के लगातार प्रयास कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान के स्वार्थी रवैए ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) को दक्षिण एशिया में आंतरिक क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने से रोक दिया है। मगर भारत ने द्विपक्षीय व्यापार संधियों और समझौतों से छोटी अर्थव्यवस्थाओं के साथ विदेश व्यापार और निर्यात रणनीति को सकारात्मक विकल्प दिए हैं। इसके अलावा भारत ने अपनी तरफ से दक्षिण एशिया सहित सबसे कम विकसित देशों को एकतरफा शुल्क मुक्त और शुल्क तरजीह योजना की पेशकश की है। भारत-आसियान व्यापार भी बढ़ कर वर्ष 2022-23 में 131.58 अरब डालर हो गया है। साथ ही, भारत आसियान देशों में निर्यात की नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है।

एक ओर 15 नवंबर, 2020 को अस्तित्व में आए दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते 'रीजनल कांप्रिहेंसिव इकोनामिक पार्टनरशिप' (आरसेप) में भारत ने अपने आर्थिक और कारोबारी हितों के मद्देनजर शामिल होना उचित नहीं समझा, वहीं 'आरसेप' से दूरी के बाद भारत एफटीए की डगर पर आगे बढ़ने की नई सोच के साथ आगे बढ़ा है। इस समय भारत विदेश व्यापार नीति को नया मोड़ देते हुए दुनिया के प्रमुख देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते की डगर पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे दुनिया में

यह संदेश जा रहा है कि भारत के दरवाजे वैश्विक व्यापार और कारोबार के लिए खुल रहे हैं। भारत ने अब तक तीन एफटीए किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच मई 2022 में लागू द्विपक्षीय कारोबार में पिछले दो वर्षों में 15 फीसद की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आस्ट्रेलिया के

> जिस तरह विकसित अर्थव्यवस्था वाले कई देश लंबे समुद्री आवागमन से पहुंचने वाले दूरदराज के देशों के बजाय अपने तट के आसपास के देशों में कारोबार पर जोर दे रहे हैं, वैसी रणनीति पर भारत को भी ध्यान देना होगा। हालांकि भारत को दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा निर्यात में तुलनात्मक रूप से बढ़त हासिल है, लेकिन यह बात ध्यान में रखनी होगी कि अब सेवा निर्यात के क्षेत्र में भी लगातार प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में भारत से डिजिटल सेवा निर्यात में तेजी से वृद्धि के लिए सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता, उत्कृष्टता तथा सुरक्षा को लेकर और अधिक प्रयास करने होंगे। भारत को अपने निर्यात में विविधता लाने और अन्य उभरते क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

अलावा विगत 10 मार्च को भारत और चार यूरोपीय देशों के समूह 'यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन' (ईएफटीए) के बीच निवेश और वस्तुओं तथा सेवाओं के दोतरफा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया एफटीए भी अत्यधिक उपयोगी है। लेकिन अब एफटीए से संबंधित देश के साथ निर्यात बढ़ाने पर अधिक ध्यान देना होगा।

अब स्थिति यह है कि दुनिया के कई विकसित और विकासशील देश भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने को उत्सुक हैं, दुनिया देख रही है कि भारत सबसे तेजी से आर्थिक विकास की डगर पर बढ़ रहा है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, सबसे अधिक कौशल प्रशिक्षण के अभियान, बढ़ता सेवा क्षेत्र, बढ़ते निर्यात और अर्थव्यवस्था के बाहरी झटकों से उबरने की क्षमता नए भारत के निर्माण की बुनियाद बन सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक पंख लगे दिखाई दे रहे हैं। घरेलू संरचनात्मक सुधार, विनिर्माण, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, बुनियादी ढांचे में निवेश और हरित ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ने से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रति वर्ष अधिक धन भेजने के साथ भारत को तकनीकी विकास के लिए मदद बढ़ी है। दुनिया के जी-20 देशों में भारत की नई अहमियत और दुनिया में मजबूत लोकतंत्र के रूप में भारत की पहचान इसके विकास को तेज रफ्तार दे रही है। ये सारी बातें भारत के लिए नए एफटीए से निर्यात बढ़ाने की नई संभावनाओं की बड़ी आधार हैं।

निस्संदेह इस वर्ष जब वैश्विक व्यापार में आर्थिक निराशाओं का दौर है, तब भारत को अपने विदेश व्यापार निर्यात का स्तर बनाए रखने के लिए कुछ और मजबूती से रणनीतिक कदम उठाने होंगे। भारत के लिए पड़ोसी देशों, आसियान देशों के साथ विदेश व्यापार बढ़ाने के साथ-साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर अधिक यकीन करना होगा। भारत द्वारा ओमान, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, इजराइल, 'गल्फ कंट्रीज काउंसिल' और यूरोपीय संघ के साथ भी एफटीए को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप देने के साथ-साथ ध्यान देना होगा कि नए एफटीए से भारत का निर्यात बढ़े और आयात का ढेर न लगे। भारत द्वारा चीन से आयात भी नियंत्रित करने होंगे।

जिस तरह विकसित अर्थव्यवस्था वाले कई देश लंबे समुद्री आवागमन से पहुंचने वाले दूरदराज के देशों के बजाय अपने तट के आसपास के देशों में कारोबार पर जोर दे रहे हैं, वैसी रणनीति पर भारत को भी ध्यान देना होगा। हालांकि भारत को दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी सेवा निर्यात में तुलनात्मक रूप से बढ़त हासिल है, लेकिन यह बात ध्यान में रखनी होगी कि अब सेवा निर्यात के क्षेत्र में भी लगातार प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में भारत से डिजिटल सेवा निर्यात में तेजी से वृद्धि के लिए सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता, उत्कृष्टता तथा सुरक्षा को लेकर और अधिक प्रयास करने होंगे। भारत को अपने निर्यात में विविधता लाने और अन्य उभरते क्षेत्रों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाली नई सरकार नई रणनीति के साथ निर्यात बढ़ाने की डगर पर आगे बढ़ेगी। उम्मीद है कि नई सरकार चालू वित्तवर्ष 2024-25 में वस्तु निर्यात को 500 अरब डालर के संभावित स्तर पर पहुंचाने के लिए निर्यात चुनौतियों से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों से देश के निर्यातों को बचाते हुए आगे बढ़ेगी। साथ ही सरकार वर्ष 2030 तक 200 अरब डालर का निर्यात लक्ष्य भी प्राप्त करने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ती दिखाई देगी।

विस्तार और संकुचन

एकता कानूनगो बक्षी

विस्तार और संकुचन दो विरोधाभासी शब्द ही नहीं हैं, बल्कि इनसे ऐसे संदर्भ निकलकर आते हैं जिनसे जीवन के बड़े महत्त्वपूर्ण विमर्श भी निकलते हैं। आमतौर पर हमें विकास की खूब चर्चा सुनाई देती है, लेकिन कई बार हम विस्तार को ही विकास मान लेने की भूल कर जाते हैं। इसी तरह संकुचन और सिमट जाने में भी बहुत बारीक अंतर होता है। हमारे समाज में हमने विस्तार को बहुत अधिक महत्त्व दिया है। परिवार, पूंजी, धर्मों, विचारधाराओं का विस्तार। विस्तार हमें हमेशा शक्तिशाली महसूस कराता है, पर विस्तार का दबाव हमें एक बेलगाम होड़ में भी सम्मिलित कर देता है। विस्तार की आकांक्षा में एक किस्म की हड़बड़ाहट भीतर बनी रहने लगती है। हमारे पास जो भी होता है, हम उसकी खींचतान कर उसे विस्तृत कर संतुष्टि महसूस करने लगते हैं।

विकास और विस्तार हमें आपस में जुड़े हुए नजर आते हैं, पर इन दोनों के बीच बहुत फर्क है। विस्तार उन चीजों का होता है जो पहले ही मौजूद हैं। जिनके विस्तार से कई वर्गों के जीवन की गुणवत्ता और अधिक बेहतर हो सकती है, जबकि विकास हर वर्ग, हर क्षेत्र की मूलभूत जरूरतों को पूरा करते हुए अपनी नींव स्थापित करता है और धीरे-धीरे उस पर काम करते हुए विकसित होने की एक लंबी संघर्षपूर्ण प्रक्रिया से होते हुए गुजरता है। विस्तार विकास के बाद आने वाली अवस्था है और उसका आना तभी सही माना जा सकता है, जब सभी संबंधित पक्षों का सम और सर्वांगीण विकास संभव हो सका हो। बिना इसके विस्तार का कोई औचित्य ही नहीं है। जब नींव ही नहीं बनी है, तो उस पर किस तरह की इमारत बन सकेगी और उनमें कौन रहेगा, जिनके पास पहले से ही इमारत मौजूद है। ऐसे में विस्तार बिना विकास का हो जाता है, मानो शरीर के भीतर प्राण ही नहीं। किसी और के दुख पर भी अपने झंडे लहराने में ऐसा विकास कभी हिचक नहीं करेगा।

विस्तार से बिल्कुल विपरीत प्रकृति का होता है सिमटना। संकुचन और समेट लेने में भी बहुत बारीक अंतर होता है। संकुचन के अर्थ में अपने संपूर्ण अस्तित्व में समस्त पक्षों और आधार क्षेत्र के साथ कमी होना है, जबकि समेटने में व्यक्ति अपने को सीमित करता है और दूसरों के लिए स्थान छोड़ने की विनम्र मंशा रखता है। हम इसी समेटने या सिमटने की बात यहां कर रहे हैं।

हम सभी ने अक्सर सिमटने से प्राप्त संतुष्टि को महसूस किया है। याद कर सकते हैं जब हम किसी जगह मेहमान बनकर जाते हैं, लौटते समय किस तरह हम ध्यान से अपना सब कुछ वापस अपने बैग में समेट लेते हैं। यहां तक कि कुछ लोग अपने कमरे को इतना स्वच्छ, व्यवस्थित करके जाते हैं जैसे वे वहां कभी ठहरे ही नहीं। ठसाठस भरे परिवहन में कभी न कभी खुद के शरीर को समेट लिया होगा, ताकि कोई और भी बैठ सके लंबे सफर में। कभी अपने शब्दों को भीतर ही समेट लिया होगा कि चुभ न जाए किसी अपने को। हमारी उपस्थिति से किसी को कष्ट न हो, हम इतना न ले लें कि दूसरे के लिए कुछ बचे ही न। हम कहीं किसी की प्रगति के बीच में आड़े तो नहीं आ रहे। उचित रूप से अपने को समेटते रहना अधिक शांत, विनम्र और गरिमामय रवैया लगता है जीवन को जीने का। जो भले हमें समृद्ध या सुखी नहीं बनाता हो, पर हम अधिक संतुलित और विवेकशील बने रहते हैं... अपने आप को कई मानसिक दबावों से बचा भी लेते हैं।

समेटने की प्रवृत्ति प्रकृति के भीतर भी देखने को भरपूर मिलती है। एक ओर वह विस्तार भी कर रही होती है, वहीं उसका ध्यान सबके विकास पर भी केंद्रित रहता है। विस्तार के मोह में कोई किसी का अतिक्रमण न कर लें, इस सोच के साथ संतुलन लगातार स्थापित होता रहता है। गौर से समझने पर यह भी नजर आता है कि समेटने के नियम का पालन प्राकृतिक रूप से जी रहे जीव-जंतु बड़ी ही गंभीरता से निभाते हैं। जब जंगलों के भीतर जहां मनुष्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है, वे इलाके अधिक स्वच्छ नजर आते हैं। जीव-जंतुओं की बहुतायत होने के बावजूद उनसे संबंधित चीजों को थोड़ा-सा ढूंढ़ने से ही हमें वे नजर आ जाती हैं। जिस तरह पेड़ों से सूख कर पत्ते झरकर मिट्टी में मिल जाते हैं, उसी तरह वहां रह रहे जीव-जंतु भी अपना जीवन इस स्वाभाविक प्रक्रिया से गुजरते हुए ही बिता रहे होते हैं। पेड़ों से गिरे सूखे पत्तों और जीव-जंतुओं का मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाना नियति है। प्रकृति का यही बहुत जरूरी नियम है खुद को समेट लेना। जो जितना अच्छे से अपने पूरे जीवन के क्रियाकलापों को समेट लेता है और पीछे स्वच्छ जगह छोड़ देता है, दूसरों को पल्लवित होने को, वह उतना ज्यादा मौका देता है। प्रकृति का यही संदेश है।

हम भी प्रकृति का ही हिस्सा हैं, जिसे खामोशी के साथ पूरी तरह मिट जाना है। हम कितना ही विस्तार की बात करें, असल में यह महत्त्वपूर्ण है कि हमने कितनी खूबसूरती से अपने जीवन को समेट लिया। हमने कितने लोगों के लिए नई संभावनाएं पैदा कीं। हमारी उपस्थिति से किसी को नुकसान न हुआ हो। खुद का विस्तार करते हुए कहीं हमने अपनी सीमा न लांघ दी हो। अंत में हम जब अपना सामान समेटें तो उसमें केवल अपनी कुछ ऐसी उपलब्धियां ही न हों जो बस हम और हमारे परिवार, समाज तक ही सीमित हों। समेट लेने में कहीं भी किसी प्रकार का संकुचन न हो। हमारे जीवन का विस्तार और सिमटने के बीच हमारे अपने छोटे-बड़े प्रयासों का ऐसा सूरज जरूर उगना चाहिए, जिसका प्रकाश कुछ दूर तक के अंधेरे में उजाला भरने की सामर्थ्य रखता हो।

दुनिया मेरे आगे

> सिमटने की प्रवृत्ति प्रकृति के भीतर भी देखने को भरपूर मिलती है। एक ओर वह विस्तार भी कर रही होती है, वहीं उसका ध्यान सबके विकास पर भी केंद्रित रहता है। विस्तार के मोह में कोई किसी का अतिक्रमण न कर लें, इस सोच के साथ संतुलन लगातार स्थापित होता रहता है।

अवैध का प्रसार

भयंकर आंधी तूफान के चलते मुंबई में एक त्रासद दुर्घटना के फलस्वरूप सोलह लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि काफी लोग बुरी तरह घायल हो गए। मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण एक बड़ा होर्डिंग और एक टावर धराशायी हो गया। दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता तो विस्तृत जांच-पड़ताल के बाद ही चल सकेगा, पर मुंबई महानगर निगम द्वारा दी गई प्रारंभिक जानकारी से उजागर हुआ है कि धराशायी हुआ यह विशालकाय होर्डिंग अवैध था। मुंबई महानगर महाराष्ट्र की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है और इतने महत्त्वपूर्ण और व्यवस्थित महानगर में किसी पेट्रोल पंप के पास ऐसा अनधिकृत निर्माण वाकई चौंकाने वाला है। मौसम में बदलाव के कारण घटित हादसों को तो नियति माना जा सकता है, लेकिन किसी होर्डिंग का अवैध होना निश्चित रूप से एक भयंकर भ्रष्टाचार का उदाहरण है। सबसे पहले इस अनधिकृत होर्डिंग के निर्माण के लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की भयावह और जानलेवा दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लग सके।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

पाक की मुश्किल

पाकिस्तान इन दिनों आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपैया की हालत से गुजर रहा है। शायद इसीलिए वहां की सरकार कर संग्रह को बढ़ाने के लिए समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों पर सख्ती से पेश आ रही है। पिछले महीने देश के कर संग्रह निकाय ने पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण को उन लोगों के पांच लाख से अधिक सिम को बंद करने का आदेश दिया, जिन्हें कर दाखिल करने की आवश्यकता थी, लेकिन जो सामने नहीं आ रहे थे। फिलहाल इसे अदालत में चुनौती दिए जाने के बाद इस पर स्थगनादेश जारी हो गया है। दरअसल, पांच लाख से अधिक सिम को बंद करने से सालाना एक अरब रुपए का नुकसान होगा। दूरसंचार कंपनी ने तर्क रखा कि सरकार द्वारा लिया गया निर्णय संविधान के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है, जो व्यापार, व्यवसाय और पेशे की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अब देखना होगा कि पाकिस्तानी हुक्मरान आगे क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि यह सब शक्ति सरकार खुद से नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के आदेश पर उठा रही है।

– जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर

समझौते से उम्मीद

ईरान के चाबहार बंदरगाह का प्रबंधन भारत को मिल जाने का दस वर्षीय समझौता चीन और पाकिस्तान के लिए अंगद का पैर साबित होगा। पाकिस्तान में चीन द्वारा विकसित वेब-पोर्ट ग्वादर बंदरगाह का नियंत्रण कर भारत के व्यापार तथा सैन्य गतिविधि को बाधित करने की मंशा का यह जवाब है। यह देश को अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों को जोड़ने में पाकिस्तान को दरकिनार कर महत्त्वपूर्ण बाइपास के रूप में काम आएगा। इस बंदरगाह से आयात-निर्यात और सैन्य गतिविधियों पर नियंत्रण की राह आसान होगी। ईरान से सौहार्दपूर्ण रिश्तों के कारण देश के लिए एक ऐसी राह खुली है, जिससे विदेश व्यापार की गतिविधि तेज होगी। चाबहार समझौता देश को कामयाबी हासिल करने में मील का पत्थर साबित होगा और चीन-पाकिस्तान के खुन्नस भरे इरादों पर लगाम लगेगी।

– हुकुम सिंह पंवार, टोड़ी, इंदौर

जीवन की यात्रा

जीवन एक अद्भुत यात्रा है, जिसमें हर क्षण नए अनुभव और सबक छिपे हुए हैं। जीवन के रास्ते में कई उतार-चढ़ाव, मोड़ और बाधाएं आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने से ही हम मजबूत और समृद्ध होते हैं। जब हम किसी नए अनुभव से गुजरते हैं, तो हमारी दृष्टि बदलती है और हम दुनिया को एक नए नजरिए से देखते हैं। आनंद और दुख, सफलता और विफलता, प्यार और घृणा, सभी इस यात्रा का हिस्सा हैं। यही जीवन की विविधता है जो इसे रोमांचक और रहस्यमय बनाती है। इस यात्रा के दौरान हम कई लोगों से मिलते हैं जो हमारे जीवन में एक विशेष स्थान रखते हैं। कुछ थोड़े समय के लिए आते हैं और कुछ हमेशा के लिए साथ निभाते हैं। ये रिश्ते भी अपने आप में एक अनुभव हैं जो हमें जीवन की गहराई समझने में मदद करते हैं। जितना ज्यादा हम जीवन से सीखेंगे, उतना ही अधिक हम समृद्ध होंगे।

– चंदन कुमार नाथ, गुवाहाटी, असम

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

नई दिल्ली

www.readwhere.com

दैनिक जागरण

कर्म की पूंजी से ही सफलता का प्रतिफल प्राप्त होता है

गुणवत्ता पर सवाल

सिंगापुर, हांगकांग के बाद नेपाल ने जिस तरह कुछ भारतीय कंपनियों के मसालों के आयात पर पाबंदी लगाई, वह चिंताजनक है। इसलिए और भी अधिक, क्योंकि इस बीच न्यूजीलैंड, अमेरिका आदि ने भी यह कहा है कि वे भारत से आयात होने वाले मसालों की गुणवत्ता की जांच करेंगे। यह ठीक है कि एक के बाद एक देशों की ओर से भारतीय मसालों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जाने पर सरकार ने यह कहा है कि वह नए मानक तैयार करने के साथ ही यह भी देखेगी कि भारतीय मसाला कंपनियों के खिलाफ विभिन्न देश जो कदम उठा रहे हैं, उसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है, लेकिन अच्छा होता कि सरकार तभी चेत जाती, जब सिंगापुर और हांगकांग ने एमडीएच एवं एवरेस्ट कंपनियों के मसालों में हानिकारक पदार्थ पाए जाने की शिकायत करते हुए उनके आयात पर पाबंदी लगा दी थी। चूंकि भारत मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक है और उनके निर्यात से देश को अच्छी-खासी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, इसलिए भारतीय मसाला बोर्ड के साथ-साथ सरकार को समय रहते सजगता दिखानी चाहिए थी। मसालों की गुणवत्ता को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। कई बार यह सामने आ चुका है कि देश में बिकने वाले विभिन्न कंपनियों के मसालों की गुणवत्ता ठीक नहीं होती। उनमें अखाद्य वस्तुएं तक मिलाई जाती हैं।

बात केवल मसालों की ही नहीं है। अन्य अनेक खाद्य एवं पेय पदार्थों के साथ-साथ दवाओं की गुणवत्ता की भी है। यह किसी से छिपा नहीं कि किस तरह कुछ देशों ने भारत से आयात होने वाली खांसी की दवा को विषाक्त बताते हुए उस पर पाबंदी लगाई थी। इसके बाद भारत सरकार को कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ा था। प्रश्न यह है कि आखिर भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता पर दूसरे देशों में सवाल उठने के बाद ही सरकार और उसकी एजेंसियां क्यों चेतती हैं? भारत में खाद्य एवं पेय पदार्थों के साथ दवाओं की गुणवत्ता के साथ समझौता होता ही रहता है। यह इसीलिए होता है, क्योंकि जिन पर भी यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि मानकों से कोई समझौता न होने पाए, वे लापरवाही का परिचय देते हैं। यह कहने में संकोच नहीं कि इसका कारण संबंधित अधिकारियों का भ्रष्टाचार है। यह निराशाजनक है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण न तो भारतीय कंपनियों के उत्पादों की गुणवत्ता की सही तरह छानबीन कर पाता है और न ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों की। अब जब भारतीय उत्पादों का निर्यात बढ़ रहा है, तब सरकार को यह सुनिश्चित करना ही होगा कि न केवल देश में बिकने वाले उत्पादों की गुणवत्ता सही हो, बल्कि निर्यात होने वाले उत्पादों की भी। सरकार के साथ ही उद्यमियों को भी चेतना होगा। उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता को विश्वस्तरीय और विश्वसनीय बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न करने होंगे।

स्वास्थ्य के लिए

दवा का उपयोग लोग इसलिए करते हैं ताकि उन्हें बीमारी से मुक्ति मिले। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रक संगठन (सीडीएससीओ) हर माह ड्रग अलर्ट जारी कर ऐसी दवाओं की सूची जारी करता है, जो गुणवत्ता की कसौटी पर खरी नहीं उतरती हैं। अब सीडीएससीओ ने हर माह ड्रग अलर्ट के साथ नकली दवाओं की जानकारी भी जारी करने की पहल की है। पहली बार पांच नकली दवाओं की जानकारी साझा की गई है। लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की दिशा में यह बड़ी पहल है। आमतौर पर लोगों को पता नहीं होता कि जो दवा वे खा रहे हैं, वह असली है या नकली। दवा की गुणवत्ता के बारे में भी वे अनभिज्ञ रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ फार्मा हब के रूप में पहचाना जाता है। इसके अलावा ऊना, सिरमौर, कांगड़ा में भी दवाओं का उत्पादन होता है। दवा उद्यमियों के साथ कई बार ऐसे लोग इस उद्योग में शामिल हो जाते हैं, जिन्हें सिर्फ मुनाफे से मतलब रहता है। उन्हें लोगों की सेहत की कोई चिंता नहीं होती। पिछले कुछ समय से नकली दवाओं के उत्पादन के मामले भी ऊना एवं बद्दी जिलों में सामने आए हैं। किसी भी उद्योग की विश्वसनीयता उसके उत्पाद पर निर्भर करती है, लेकिन चिंता की बात है कि हिमाचल के उद्योगों में बन रही दवाओं पर हर माह सवाल उठ रहे हैं। अप्रैल में भी प्रदेश की सात दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरीं। नकली दवाओं का अलर्ट जारी करने में राज्यों को सक्रियता से योगदान देना चाहिए। फरवरी में सीडीएससीओ ने जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए सभी राज्यों को लिखा था, लेकिन हिमाचल समेत कई प्रमुख राज्यों ने सूची नहीं दी। मामला लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है, इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर कोताही नहीं होनी चाहिए।

नकली दवाओं पर शिकंजा कसने के लिए सीडीएससीओ की पहल सराहनीय है

गुलाम जम्मू-कश्मीर की आवाज बने भारत

दिव्य कुमार सोती

भारत को गुलाम जम्मू-कश्मीर में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए

अवधेश राजपूत

पाकिस्तान में बलूचिस्तान और पश्तून इलाकों में तो वर्षों से विप्लव का दौर चल रहा था, पर अब उसके अवैध कब्जे वाला गुलाम जम्मू-कश्मीर भी आक्रोश-असंतोष से अछूता नहीं है। गुलाम जम्मू-कश्मीर में बढ़ती महंगाई, बिजली-पानी के अभाव और प्राकृतिक संसाधनों की इस्लामाबाद द्वारा की जा रही लूट को लेकर आक्रोश तब चरम पर पहुंच गया, जब एक स्थानीय प्रभावशाली सामाजिक संगठन अवामी एक्शन कमेटी ने इन मुद्दों को लेकर गुलाम जम्मू-कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर कूच करने की घोषणा कर दी। इस मार्च को भारी जनसमर्थन मिला और प्रदर्शनकारियों और पुलिस में भारी झड़पों के चलते पाकिस्तान सरकार को पाक रेंजर्स और फौज को भी सड़कों पर उतारना पड़ा। इस हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। मामला इतना बिगड़ गया कि प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को हस्तक्षेप करना पड़ा और प्रदर्शनकारियों की अधिकतर मांगें माननी पड़ीं, जिनमें आटे की प्रत्येक बोरी पर 2,100 पाकिस्तानी रुपये की सब्सिडी देने का वादा भी शामिल है। चूंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस विरोध-प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तान की छीछालेदर हो रही है तो इससे बचने के लिए उसने गुलाम जम्मू-कश्मीर में स्थित मंगला और नीलम-झेलम बिजली परियोजनाओं से सस्ती बिजली भी इस क्षेत्र को मुहैया कराने और यहां के संसाधन भी वहीं लगाने जैसे आश्वासन दिए। हालांकि पाकिस्तान के मूल चरित्र और उसकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए ये सब वादे शायद ही कभी पूरे किए जाएंगे।

ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या भविष्य में यह नागरिक असंतोष पाकिस्तान से अलगाववाद की प्रवृत्ति में भी बदल सकता है? और क्या मौका मिलने पर गुलाम जम्मू-कश्मीर को भारत में शामिल किया जा सकता है? यदि हां तो क्या ऐसा करना युक्तियुक्त होगा? गुलाम जम्मू-कश्मीर को पाक अधिकृत गिलगित-बाल्टिस्तान से अलग करके देखने की आवश्यकता है। गुलाम जम्मू-कश्मीर भारत की स्वतंत्रता और पाकिस्तान के साथ कश्मीर को लेकर 1947 में हुए पहले युद्ध से बहुत पहले से इस्लामिक कट्टरपंथ का गढ़ रहा है। इस इलाके में मीरपुरी मुसलमानों की बहुतायत है, जो कश्मीरी भाषी नहीं हैं। मीरपुरी मुस्लिम समाज इस्लामिक कट्टरपंथ में प्रभावित रहा है और पाकिस्तान के जम्मू-कश्मीर पर पहले हमले के समय मीरपुरी मुसलमानों ने वहां रहने वाले हजारों हिंदुओं और सिखों की हत्या कर दी थी। बाकी बचे लोगों को भारत में शरण लेनी पड़ी थी। मीरपुरी मुसलमानों का आइएसआइ द्वारा स्थापित वैश्विक जिहाद कांप्लेक्स में भी बड़ा योगदान रहा है। भारत में हुए अधिकांश आत्मघाती आतंकी हमलों में मीरपुरी और पंजाबी मुसलमान आतंकी ही शामिल रहे हैं।

मीरपुरी समाज में कट्टरपंथ कितनी गहरी जड़ें जमा चुका है, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि ब्रिटेन जाकर बसे मीरपुरी मुसलमानों ने ही 7 जुलाई, 2005 के लंदन बम धमाकों को अंजाम दिया था, जिसमें 56 लोग मारे गए थे और 784 लोग घायल हुए थे। भारत की धरती पर किसी यूरोपीय व्यक्ति द्वारा आत्मघाती आतंकी हमला करने के एकमात्र मामले का भी मीरपुरी कनेक्शन रहा है। ब्रिटेन के बर्मिंघम में पैदा हुए मीरपुरी मुस्लिम अब्दुल्ला ने बीच श्रीनगर में खुद को बम से उड़ा दिया था। रा के पूर्व अधिकारी और आतंकवाद निरोधक मामलों के विशेषज्ञ बी. रमन ने लिखा था कि मीरपुरी मुसलमान भारत के विरुद्ध जिहादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेने में सबसे आगे रहे हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे तमाम आतंकी संगठनों के कैंप दशकों से इस इलाके में सक्रिय रहे हैं और ये आतंकी गुलाम जम्मू-कश्मीर के मीरपुरी समाज में घुले-मिले हैं। ऐसे में 40 लाख की घनी आबादी वाली इस पट्टी को भारत में शामिल करना और मुख्यधारा से जोड़ पाना बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है, क्योंकि सदियों का कट्टरपंथ कुछ सालों में समाप्त नहीं होने वाला है। दूसरी समस्या यह है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले इस क्षेत्र को बिना सैन्य कार्रवाई के भारत में शामिल नहीं किया जा सकता।

यदि नागरिक असंतोष बहुत अधिक बढ़ भी जाए तो भी पाकिस्तानी फौज इस इलाके को हाथ से जाने नहीं देगी और पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए भारत को अंततोगत्वा 1971 में बांग्लादेश के मामले की तरह ही सैन्य हस्तक्षेप करना ही पड़ेगा। हालांकि इस इलाके के पहाड़ी भूगोल के चलते यह लंबे छापामार संघर्ष में बदल सकता है। साथ ही इस युद्ध में चीन द्वारा भी मोर्चा खोले जाने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। अनुच्छेद-370 हटाए जाने और जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के संवैधानिक दर्जे में परिवर्तन मात्र ने ही चीन की सेना को पूर्वी लद्दाख में ला खड़ा किया है। अगर भारत गुलाम जम्मू-कश्मीर के हिस्सों को अपने नियंत्रण में लेता है तो चीन का सैन्य हस्तक्षेप अवश्य होगा, क्योंकि अमेरिका के साथ किसी भावी युद्ध में चीन के आपूर्ति मार्ग पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के इन हिस्सों से होकर जाते हैं और वह उनमें अरबों डालर निवेश कर चुका है। ऐसे में अच्छा यह होगा कि भारत मौका आने पर त्वरित सैन्य कार्रवाई कर हाजी पीर दर्रे जैसे सामरिक इलाकों को नियंत्रण में ले, जिनके जरिये पाकिस्तान भारत में आतंकी घुसपैठ कराता है। इससे जम्मू-कश्मीर में आतंकी घुसपैठ लगभग बंद हो जाएगी और भविष्य के किसी बड़े सैन्य संघर्ष में भारत की स्थिति मजबूत होगी। साथ ही, भारत पर नई जनसंख्या का भार भी नहीं आएगा।

मीरपुर जैसे क्षेत्रों की जिहादी विचारधारा से ओतप्रोत आबादी को पाकिस्तान के कुशासन में तब तक रहने दिया जाना चाहिए, जब तक वे स्वयं आत्ममंथन कर इस जहरीली विचारधारा को नकारते हुए न दिखें। हां, तब तक भारत को गुलाम जम्मू-कश्मीर में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों पर आवाज उठाते रहना चाहिए, क्योंकि तकनीकी रूप से वह हमारी ही भूमि है। इसके लिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा में इस क्षेत्र की खाली पड़ी सीटों में से कुछ पर विधायक भी नामित किए जा सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के अत्याचारों से त्रस्त होकर भारत से शरण मांगी हो। यह कश्मीर को लेकर पाकिस्तान द्वारा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर किए जाने वाले प्रोपेगंडा की सही काट साबित होगा।

(लेखक काउंसिल आफ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

राजनीतिक अस्थिरता का शिकार नेपाल

डा. ऋषि गुप्ता

नेपाल के वामदलों के स्वार्थ का खामियाजा नेपाल की राजनीति और वहां की जनता को भुगतना पड़ रहा है

विश्वासमत हासिल करने के बाद पुष्प कमल। प्रेट्र

बीते दिनों नेपाल में वामदलों की गठबंधन वाली सरकार ने संसद के निचले सदन (राष्ट्रीय सभा) में विश्वासमत प्राप्त कर लिया। यह चौथी बार है कि जब प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' पिछले 18 महीने के भीतर संसद के पटल पर विश्वासमत सिद्ध करने के लिए खड़े हुए थे। दरअसल गत 13 मई को उपप्रधानमंत्री उपेंद्र यादव के समूह वाली जनता समाजवादी पार्टी आपसी फूट के चलते प्रचंड सरकार से अलग हो गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री प्रचंड ने संविधान की धारा 100(2) के अंतर्गत विश्वासमत का प्रस्ताव रखा, जो 157 मतों के साथ बहुमत से पारित हो गया। नेपाल में वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री प्रचंड के नेतृत्व में वामदल वाली सरकार बनी थी, लेकिन वह ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। फिर प्रचंड ने प्रजातांत्रिक पार्टियों के साथ मिलकर दूसरी बार सरकार बनाई, जिसमें नेपाली कांग्रेस भी शामिल थी, पर वह भी अधिक दिनों तक नहीं टिक सकी। तीसरी बार प्रचंड ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी आफ नेपाल (एमाले), रवि लामिछाने की स्वतंत्रता पार्टी और उपेंद्र यादव की जनता समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, जो हाल में उपेंद्र यादव के इस्तीफे के चलते संवैधानिक संकट में आ गई। उसके चलते प्रचंड को एक बार फिर बहुमत हासिल करना पड़ा।

नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता सामान्य बात हो गई है। नेपाल में 2008 में लोकतंत्र की स्थापना के बाद से चार बार राष्ट्रीय चुनाव हो चुके हैं। वहां अब तक 12 से ज्यादा प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन कोई भी सरकार पांच साल की अवधि पूरी करने में असमर्थ रही है। मौजूदा वामदल वाली सरकार में प्रधानमंत्री प्रचंड की माओवादी केंद्र पार्टी और केपी शर्मा ओली की एमाले दो धुर विरोधी समूह शामिल हैं, जिनके बीच शक्ति और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर लगातार खींचतान होती रही है। हालांकि ओली ने प्रचंड सरकार को समर्थन दिया है, लेकिन पिछले कई मौकों पर सरकार केवल इसी वजह से गिरी, क्योंकि प्रचंड और ओली, दोनों ही प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करते रहे। इस बार भी प्रचंड सरकार को भले विश्वासमत मिल गया हो, लेकिन यह राजनीतिक स्थिरता की कोई गारंटी नहीं है। आने वाले दिनों में अगर वाम सरकार फिर गिरी तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि ओली कभी भी प्रचंड सरकार से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि 275 सदस्यों वाली राष्ट्रीय सभा में जो 165 सदस्य सीधे चुनकर आए हैं, उनमें से प्रधानमंत्री प्रचंड की माओवादी केंद्र के पास कुल 32 सीटें हैं, जबकि एमाले के पास 78 सीटें हैं। राजनीतिक गणित के हिसाब से गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते एमाले को प्रधानमंत्री पद का दावेदार होना चाहिए, लेकिन प्रचंड की हठ के चलते एमाले प्रमुख ओली को अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं से समझौता करना पड़ा। यदि ओली फिर से प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी करते हैं तो सरकार का गिरना तय है।

राजनीतिक दलों के स्वार्थ के चलते नेपाल आज सबसे अधिक पूर्व प्रधानमंत्रियों एवं मंत्रियों का ठिकाना बन गया है। वामदल नेपाल की विदेश नीति के साथ लगातार खिलवाड़ करते आ रहे हैं, जिसका सीधा नुकसान वहां की जनता को हो रहा है। नेपाल के एक ओर एक विस्तारवादी देश चीन है और बाकी तीन तरफ से भारत। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि नेपाल एक स्थिर विदेश नीति अपनाए, लेकिन पिछले 75 वर्षों के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में वह ऐसा करने में असमर्थ रहा है। भारत लंबे समय से नेपाल के विकास का समर्थक रहा है। भारत के मित्रवत व्यवहार के बावजूद नेपाल के वामपंथी दल हमेशा भारत विरोधी रुख अपनाते रहे हैं। एमाले जैसी पार्टियों ने पिछले 10 वर्षों से भारत विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व किया है। हाल में नेपाल के राष्ट्रपति के आर्थिक सलाहकार को इसलिए इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने वामपंथी सरकार के उस फैसले का विरोध किया, जिसके तहत वह सौ रुपये के नोटों पर एक विवादित नक्शा छाप रही है। यह वही नक्शा है, जिसे नेपाल की संसद ने 2020 में पारित किया था, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को नेपाल ने अपना बताया है। माना जा रहा है कि प्रचंड ने ओली के दबाव के चलते ऐसा किया।

ओली अपने भारत विरोध और चीन समर्थन के लिए जाने जाते हैं। उनका यह रवैया नेपाल के हित में कभी नहीं रहा। यह बस उनके लिए राजनीतिक फायदा हासिल करने का एक जरिया बनकर रह गया है। गत दिनों नेपाल के उपप्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठा भी अपनी पहली विदेश यात्रा पर चीन गए थे। वामदलों के इस भारत विरोध के बावजूद ज्यादातर नेपाली जनता चीन पर विश्वास नहीं करती। चीन छोटे देशों को अपने 'ऋण जाल' में फंसाकर उनकी राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य व्यवस्थाओं को अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है। वामदलों की अदूरदर्शिता के कारण नेपाल भी चीन के चंगुल में फंसता जा रहा है। उनकी राजनीति का आधार ही भारत विरोध बन गया है, जो न केवल भारत के साथ नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों को खराब कर रहा है, बल्कि उसकी प्रगति को भी बाधित कर रहा है। नेपाल की राजनीतिक दुर्गति के चलते आज वहां के लाखों युवा रोजगार और अच्छे जीवन की खोज में लगातार पलायन कर रहे हैं। यदि नेपाल के नेता स्वार्थ त्यागकर देशहित में राजनीतिक अस्थिरता को दूर करें तो वह विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से घिरे होने का सबसे बड़ा फायदा उठा सकता है।

(लेखक एशिया सोसायटी पालिसी इंस्टीट्यूट, दिल्ली में सहायक निदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

बुराई कम कैसे हो?

जीवन में उदय-अस्त, हर्ष-विषाद, सफलता-असफलता से जुड़ी दोनों ही स्थितियां देखने को मिलती हैं, लेकिन कुछ लोग जन्म से ही अवसान की अवस्था में रहते हैं। इसका कारण है अज्ञानता, अहंकार, अभिमान। इन स्थितियों के कारण उनका जीवन नष्ट हो जाता है। वे जानते नहीं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा? क्या उचित है क्या अनुचित है? शराब पीने का क्या नुकसान है, इसे जानते नहीं और पीने लग जाते हैं। यह अज्ञान है। कुछ लोग परिणाम जानते हैं, लेकिन अपने प्रमाद, अहंकार के कारण बुराई को गले लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें ज्ञान का अहंकार है, इसलिए बुराई को जानते हुए भी अहंकारवश अपना लेते हैं कि मैं शक्तिशाली हूं, मेरा क्या बिगड़ने वाला है। विश्व में अज्ञान, प्रमाद और अहंकार से अस्त होने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जो स्वयं तो नष्ट होते ही हैं दूसरों के विनाश के बारे में भी सोचते हैं। बुराइयों से घिरे ऐसे लोगों की सबसे बड़ी विसंगति यह है कि वे अकेले में बेचैन हो जाते हैं, उन्हें अधूरापन महसूस होता है। इसलिए वे कुछ और लोगों को अपनी संगत में लेने का प्रयत्न करते हैं। प्लेटो का कथन है कि अति प्रायः प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है और विपरीत दिशा में परिवर्तन लाती है, चाहे वह ऋतु में हो अथवा व्यक्ति या शासन में।

सत्य है कि बुराई का जितनी तेजी से संक्रमण होता है, उतना अच्छाई का नहीं होता। हमें विचार करना है कि बुराई कम कैसे हो? बुराई के परिणाम के प्रति लोगों को अवगत कराया जाए। बड़ी सफलता का संकल्प लिया जाए। अगर आप बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्वयं को अपनी सीमाओं से परे धकेलना होगा। अपने आपको एक उच्च मानसिक अवस्था में ले जाना होगा। और आपको यह सब स्वयं करना होगा। कोई और आपके लिए यह नहीं कर सकता।

ललित गर्ग

घटते पेड़ों से बिगड़ती प्रकृति की लय

देवेंद्रराज सुथार

भारतीय खेतों से छायादार वृक्षों का लुप्त होना एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है

नेचर सस्टेनेबिलिटी जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भारत में छायादार पेड़ों की कम होती संख्या पर गहरा प्रकाश डाला है। पिछले पांच वर्षों में भारतीय खेतों से नीम, महुआ, जामुन और शीशम सहित लगभग 53 लाख छायादार पेड़ गायब हो गए हैं। दरअसल धान की पैदावार बढ़ाने के लिए किसान इन पेड़ों को बाधा मान रहे हैं। इसलिए इन्हें तेजी से साफ कर रहे हैं।

यह प्रवृत्ति चिंताजनक है, क्योंकि देश की 56 प्रतिशत भूमि कृषि के लिए है और केवल 20 प्रतिशत वन के रूप में वर्गीकृत है। कृषि क्षेत्रों में हरियाली बनाए रखने और यहां तक कि विस्तार करने की महत्वपूर्ण क्षमता है। हालांकि छायादार पेड़ों को हटाकर इस क्षमता को व्यवस्थित रूप से कम किया जा रहा है, जो न केवल गर्मी से राहत देने के लिए, बल्कि जैव विविधता को बनाए रखने और जलवायु को स्थिर करने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। वनों की कटाई के परिणाम पहले से ही स्पष्ट हैं। शहरी क्षेत्र अपनी प्राकृतिक छटा से वंचित होकर भीषण गर्मी में झुलस रहे हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने, कृषि स्थिरता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद छायादार पेड़ों को नष्ट करना मूर्खता ही है। वे पक्षियों, कीड़ों और अन्य वन्यजीवों की कई प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं। उनकी जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकने, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और जल संरक्षण में सहायता करती हैं। इन पेड़ों को काटकर हम न केवल तात्कालिक कृषि पर्यावरण को बाधित कर रहे हैं, बल्कि भूमि की दीर्घकालिक स्थिरता को भी खतरे में डाल रहे हैं।

छायादार वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कृषि पद्धतियों में अल्पकालिक सोच को भी दर्शाती है। हालांकि फसल उत्पादन में वृद्धि से तात्कालिक लाभ फायदेमंद लग सकता है, लेकिन दीर्घकालिक पर्यावरणीय लागत गंभीर है। मृदा क्षरण, जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन की बढ़ती समस्या ऐसे गंभीर परिणाम हैं, जिनका सामना आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ेगा। इस संकट से निपटने के लिए इन पेड़ों को उनकी कृषि प्रणालियों में एकीकृत करने वाली कृषि वानिकी प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकारी नीतियों को छायादार पेड़ों के संरक्षण और रोपण को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के इच्छुक किसानों को वित्तीय और तकनीकी सहायता मिल सके। शहर रहने योग्य बने रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए शहरी नियोजन को हरित स्थानों को प्राथमिकता देनी चाहिए। भारतीय खेतों से छायादार वृक्षों का लुप्त होना एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

उद्योग जगत का विरोध अनुचित

'माओवादी भाषा' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़ा। राहुल गांधी देश के कुछ उद्योगपतियों पर काफी पहले से ही अंगुली उठा रहे हैं और मोदी के खासमखास बता रहे हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी देश की आर्थिक व्यवस्था की मजबूती के लिए उद्योगीकरण को बढ़ावा देना जरूरी माना था। नेहरू यह मानते थे कि उद्योगों को बढ़ावा देने से ही देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो सकती है। राहुल गांधी को चाहिए कि वह इतिहास को पढ़कर देखें कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने भी उद्यमियों को देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना था। देश के हर छोटे-बड़े कारोबारी और उद्योगपति देश के हित में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। वे अपने यहां लोगों को रोजगार दिए हुए हैं जिससे उनका घर चलता है। हर बेरोजगार को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराना मुश्किल ही नहीं, बल्कि नामुमकिन है। देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में उद्योग जगत की मुख्य भूमिका है। वे देश की सरकारों को भारी मात्रा में कर देते हैं। बेशक सत्ताधारी देश को चलाने के लिए योजनाएं अमल में लाते हैं, लेकिन ये योजनाएं भी उद्योग जगत द्वारा कर के रूप में दिए पैसे के बिना कामयाब नहीं हो सकती हैं। किसानों और अन्य वर्गों को भी जो मुफ्त की सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती हैं उसमें भी देश के कारपोरेट जगत द्वारा दिए गए टैक्स का बड़ा योगदान होता है। अगर कारपोरेट जगत के कर्ताधर्ता देश से अपना कारोबार समेट लें तो इससे देश में बेरोजगारों की बाढ़ आ जाएगी। इसलिए राहुल गांधी को मोदी सरकार की अन्य गलत नीतियों का विरोध करना चाहिए, देश के कारपोरेट जगत पर बेवजह सवाल नहीं उठाने चाहिए।

raju09023693142@gmail.com

लापरवाही की कीमत

'दूषित जल का गहराता संकट' शीर्षक से लिखे आलेख में पंकज चतुर्वेदी ने दूषित जल के दुष्परिणामों का जिक्र किया है। अक्सर देश में दूषित पानी लोगों की सेहत के दुश्मन बनने की खबरें सुर्खियां बनती हैं। दूषित जल के कारण लोगों की जो सेहत खराब होती है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है सरकार, प्रशासन या फिर आमजन? दूषित जल के लिए तो सरकार और प्रशासन ही ज्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि आमजन को सरकार की तरफ से दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं में साफ स्वच्छ जल उपलब्ध करवाना मुख्य होता है, लेकिन हमारे देश के सत्ताधारियों की आदत बन चुकी है आग लगने पर कुआं खोदने की। कई बार तो कुआं खोदने की भी कोशिश नहीं करते, बस लापरवाहियों पर शिकंजा कसने का आश्वासन देकर अगली लापरवाही तक लंबी तान कर सो जाते हैं। सरकार, प्रशासन और सरकारी विभाग अपनी लापरवाही गलती कम ही मानते हैं। यह सब जानते हैं, लेकिन दूषित पानी लोगों की सेहत का दुश्मन न बने इसके लिए सरकार और प्रशासन क्यों कोई उचित कदम नहीं उठाते? क्यों आमजन को दूषित पानी के बारे क्यों जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते? महात्मा गांधी ने कहा था कि नदियां हमारे देश की नाड़ियों की तरह हैं। यदि हम उन्हें गंदा करना जारी रखेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी नदियां जहरीली हो जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो हमारी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। जिन नदियों को हम माता समझते हैं, उनका प्रदूषण हमारे लिए भी किसी शाप से कम नहीं हो सकता। जिस दिन देश का हरेक नागरिक यह समझ जाएगा कि उसका अस्तित्व नदियों की वजह से भी ही है, उस दिन से कोई भी नदियों में गंदगी नहीं डालेगा। और उसी दिन से नदियों की साफ-सफाई के सरकारी एवं गैरसरकारी प्रयास कामयाब होंगे। जल और जीवन पर्यायवाची हैं। जल प्रदूषण स्वास्थ्य का बड़ा शत्रु है। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के 400 से अधिक जिलों का जल गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुका है। भूजल में शीशा, आर्सेनिक, फ्लोराइड और क्रोमियम जैसे जानलेवा रसायन पाए गए हैं। हर साल लगभग ढाई करोड़ लोग जल प्रदूषण जनित बीमारियों के शिकार होते हैं। बच्चे दिव्यांग होते हैं।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 81

गर्मी का प्रकोप

देश के एक बड़े हिस्से में लू का प्रकोप चल रहा है। इससे लोगों की सेहत और उत्पादकता पर खतरा गंभीर हो सकता है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के मुताबिक, देश का करीब 75 फीसदी कार्यबल कृषि और निर्माण क्षेत्र में गर्मी का सीधे सामना करने वाले श्रम पर निर्भर करता है। इसके मुताबिक साल 2030 तक गर्मी के प्रकोप से जुड़ी उत्पादकता में गिरावट की वजह से दुनिया भर में कुल होने वाली नौकरियों के नुकसान में अकेले भारत का योगदान करीब 43 फीसदी तक हो सकता है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि लू का प्रसार और घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह फैलाव साल 2009 के नौ राज्यों से बढ़कर साल 2020 में 23 राज्यों तक (2020 महामारी का वर्ष था जब लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई थीं) हो गया। इसी अवधि में लू के औसत दिनों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 7.4 दिन से 32.2 दिन तक पहुंच गई। यह उत्साहजनक है कि केंद्र और राज्य सरकारों ने इस समस्या का संज्ञान लिया है और तत्परता से कदम उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए साल 2016 से ही, जब लू से 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, केंद्र सरकार ने लू की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राज्यों में कार्य योजना बनाने के लिए एक व्यापक ढांचे के रूप में राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार किए।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने निर्धारित किया है कि किसी इलाके में लू की घोषणा तब की जानी चाहिए, जब वहां वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ हो, सामान्य अधिकतम तापमान कुछ भी हो। इस मामले में सबसे उपयोगी दस्तूर यह अपनाया जाता है कि भारतीय मौसम विभाग लू की एक चेतावनी जारी करता है और इससे बचने के लिए क्या करें, क्या न करें का एक मानक पैकेज होता है। नियोक्ताओं ने इस मामले में कुछ कदम उठाए। गर्मी के संपर्क वाले काम को रात के थोड़े ठंड वाले घंटों के लिए टाल दिया दिया गया, एक ऐसा बदलाव जिसे कुछ समय पहले कृषि श्रमिकों ने अपनाया था। इन सबका नतीजा यह हुआ कि लू से संबंधित मौतों की संख्या 2015 के 2040 से तेजी से घटकर 2020 में केवल 27 रह गई है। वैसे तो ये संख्या सराहनीय हैं, लेकिन आगे के लिए बड़ी चुनौती यह है कि लू प्रबंधन को किस तरह से एक सतत अनिवार्यता के रूप में विस्तारित और संस्थागत बनाया जाए। इसके लिए सिर्फ लू की चेतावनी और परामर्श जारी करने से काम नहीं चलने वाला; सूक्ष्म और वृहद नीति स्तरों पर ठोस और व्यावहारिक नीतियां अपनाने की जरूरत है।

उदाहरण के लिए जलाशयों के जलस्तर में 35 फीसदी तक की गिरावट आ चुकी है, ऐसे में जल संकट आसन्न है, जैसा कि इस साल हम बेंगलूरु में देख चुके हैं। इसके लिए शहरी प्रशासन द्वारा सभी ऊंची इमारतों में जल संचयन प्रणाली को लागू करने के लिए तत्काल कवायद की आवश्यकता है, एक ऐसा आदेश जिसका पानी की कमी वाले शहरों में उल्लंघन अधिक देखा जाता है। नीतिगत स्तर पर, राज्य सरकारों को निश्चित तौर पर राजनीतिक नुकसान वाले कड़े कदम उठाने होंगे तथा पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में सिंचित क्षेत्रों में गन्ना और चावल जैसी पानी की अधिक खपत वाली फसलों को प्रोत्साहन देने की नीति में बदलाव करते हुए कम जल की जरूरत वाले श्री अन्न जैसे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना होगा जिनमें लोगों की सेहत में सुधार करने की क्षमता भी है।

अन्य स्पष्ट उपायों में सार्वजनिक स्थानों पर अधिक पेड़ लगाना शामिल हो सकता है जिसे कि दुबई और सिंगापुर जैसे शहरों के वास्तुशिल्प मानकों में अनिवार्य और निर्धारित किया गया है जिससे एयर कंडीशनिंग पर दबाव कम होता है। साथ ही, दफ्तरों के काम के घंटों में भी बदलाव कर दिन में थोड़ा और पहले शुरू करने और दिन के तापमान चरम से पहले समाप्त करने की व्यवस्था की जा सकती है। बिजली की मांग चरम पर होने के कारण प्रदूषण फैलाने वाले कोयले से चलने वाले संयंत्र भारी मात्रा में कोयला उठा रहे हैं। ऐसे में बैटरी भंडारण प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाने की कुछ तत्परता दिखानी होगी ताकि पवन और सौर जैसे नवीकरणीय स्रोत बिजली उत्पादन में अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। भारत, जो कि इस तरह के चलन का केंद्र बन गया है, यहां अगले दशकों में लू का जोखिम और तेजी से बढ़ने की आशंका है, इसलिए इसे पहले से काफी तेज गति से काम करना होगा।

बिनय सिन्हा

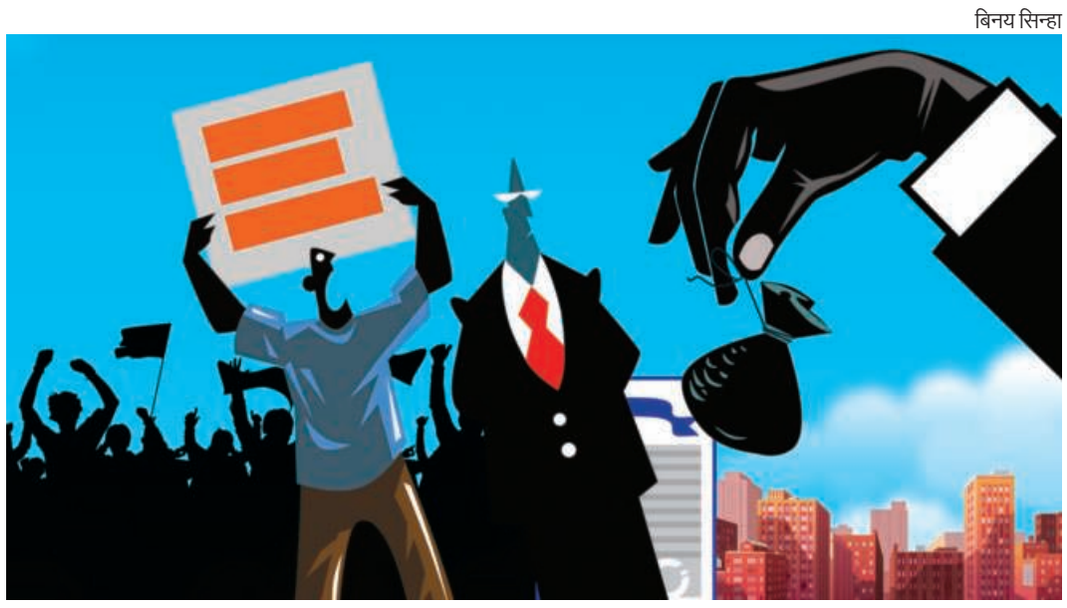

अमेरिका में प्रदर्शन और फैकल्टी की खामोशी

अमेरिकी विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शनों के बीच वहां के अकादमिक जगत के लोग खामोश क्यों हैं? बता रहे हैं टीटी राम मोहन

अमेरिकी विश्वविद्यालयों के परिसर पिछले महीने गाजा में छिड़ी लड़ाई के विरोध प्रदर्शन से उबल पड़े। फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहे ये प्रदर्शन अभी जारी हैं और अब पूरे यूरोप में फैल चुके हैं। इन प्रदर्शनों ने विश्वविद्यालयों में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर कुछ बुनियादी प्रश्न उठाए हैं। विश्वविद्यालयों के प्रशासक जो प्रायः अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ हैं उन पर प्रदर्शनकारियों को खामोश रखने का दबाव है। खुद उनकी आवाज को भी दबाया गया है। ऐसे प्रदर्शनों से निपटने के लिए विश्वविद्यालयों को अभिव्यक्ति की आजादी और परिसर में व्यवस्था बनाए रखने के बीच संतुलन कायम करना होगा। अमेरिकी सिविल लिबर्टीज यूनियन ने इसके लिए ऐसे नियम तय किए जिन पर शायद ही कोई झगड़ा हो।

पहला, कोई भी नजरिया चाहे वह जितना आक्रामक हो, उसे सेंसर नहीं करना चाहिए या अनुशासन के दायरे में नहीं लाना चाहिए। दूसरा, किसी छात्र या समूह को अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर निशाना नहीं बनाना चाहिए या धमकाना नहीं चाहिए। तीसरा, विश्वविद्यालय प्रदर्शन करने के समय और स्थान को नियंत्रित कर सकते हैं ताकि विश्वविद्यालय का सामान्य कामकाज प्रभावित न हो। चौथा, पुलिस केवल अंतिम उपाय के रूप में बनानी चाहिए। इन परिसरों के नेताओं को राजनीतिक दबाव में नहीं आना चाहिए।

विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के लिए विरोध प्रदर्शनों को इन नियमों के अधीन करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। दुख की बात है कि कई अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हालात हाथ से निकल गए। कई जगह सामान्य हालात में भी छात्रों से निपटने के लिए पुलिस और आतंकवाद निरोधक दस्तों तक को बुलाया गया। विश्वविद्यालयों की यह प्रतिक्रिया निराश कर सकती है लेकिन किसी को बहुत अधिक चकित होने की आवश्यकता नहीं।

अमेरिका विश्वविद्यालयों के परोपकारी योगदान के मामले में विशिष्ट स्तर पर है। दानकर्ता अक्सर वहां वित्तीय मदद का सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। छात्रों के शुल्क से तो विश्वविद्यालय चलाने का खर्च तक नहीं निकलता। कोई विश्वविद्यालय या कॉलेज दान से जितना फंड जुटाता है, वह अधोसंरचना, शोध और फैकल्टी में उतना ही निवेश कर सकता है। इससे उसका कद बढ़ता है। दानदाताओं को नाराज करना ठीक नहीं।

इसके अलावा विश्वविद्यालयों को सरकार से भी शोध परियोजनाओं के लिए भारी फंड मिलता है। उदाहरण के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग ऐसी फंडिंग का ऐतिहासिक स्रोत रहा है। कंपनियां भी शोध परियोजनाओं को फंड करती हैं। प्रमुख दानदाताओं, बड़ी कंपनियों और राजनेताओं ने इन परिसरों में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों को लेकर अपनी नाखुशी कभी नहीं छिपाई। अमेरिकी दानदाता और राजनेताओं ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पर विरोध प्रदर्शनों का दमन भी किया।

एक तरफ विश्वविद्यालयों और सरकार तथा दूसरी ओर निजी क्षेत्र के संबंध इतने गहरे हैं कि ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं जा सकते। छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय उन कंपनियों से दूरी बनाएं जो इजरायल से जुड़े हैं। ऐसे में मांग माने जाने के बजाय विश्वविद्यालयों के खिलाफ कदम उठाना लाजिमी था।

ऐसा नहीं है कि केवल विश्वविद्यालयों के प्रशासक ही बाहरी दबाव महसूस कर रहे हैं। फैकल्टी सदस्य भी छात्रों के वैध प्रदर्शन के पक्ष में नहीं आ पा रहे हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में 111 सदस्यों वाली विश्वविद्यालय सीनेट ने अन्य बातों के अलावा विश्वविद्यालय अध्यक्ष के पुलिस बुलाने के निर्णय की निंदा की लेकिन इसके खिलाफ मतदान नहीं किया। हार्वर्ड में करीब 300 शिक्षकों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर करके विश्वविद्यालय अध्यक्ष से मांग की कि वह प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत करें। विश्वविद्यालय के 2,400 अध्यापकों में यह संख्या बहुत छोटी है। हस्ताक्षर करने वालों में से अधिकांश मानविकी विभागों से थे। हार्वर्ड के प्रसिद्ध कानून, कारोबार, चिकित्सा और भौतिकी, रसायन तथा अर्थशास्त्र विभागों के शिक्षक सूची से मोटे तौर पर अनुपस्थित नजर आए। कुछ ही विश्वविद्यालयों में शिक्षकों ने नेतृत्व के खिलाफ अविश्वास मत जाहिर किया। ऐसा बहुत कम देखने को मिला।

आप सोच सकते हैं कि अमेरिका के तमाम नोबेल विजेता और अन्य वैचारिक नेतृत्वकर्ता कहां हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय के जोसेफ स्टिगलिट्ज जो स्वयं एक यहूदी हैं, उन्होंने 'अकादमिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप' की आलोचना की है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा, 'वे (छात्र) दुनिया में क्या हो रहा है उससे समानुभूति रखते हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मरते और घायल होते देखकर आखिर कोई कैसे प्रतिक्रिया नहीं देगा?' प्रोफेसर स्टिगलिट्ज एक अपवाद हैं जबकि अमेरिका के अकादमिक जगत में अधिकांश लोग खामोश हैं।

अमेरिका में शिक्षकों के भी दो समूह हैं: क्लिनिकल फैकल्टी अधिकतर शिक्षण करती है और वे अनुबंध पर होते हैं। वे ऐसे मसलों पर कोई रुख अपनाकर अपनी नौकरी को दांव पर नहीं लगाना चाहते। दूसरी तरह के शिक्षक वे हैं जो जिनकी नौकरी पूरी तरह सुरक्षित है और उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र तय नहीं है। ऐसा संरक्षण हासिल होने के कारण लोग उम्मीद करते हैं कि वे अकादमिक स्वायत्तता को लेकर बात करेंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। बीते दशकों में अमेरिकी अकादमिक जगत में संचालन में परिवर्तन आया है। अमेरिकी विश्वविद्यालय फैकल्टी संचालित माने जाते हैं। यानी फैकल्टी सदस्यों से उम्मीद की जाती है कि वे कॉलेज और विश्वविद्यालयों के संचालन में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। बीते दो या तीन दशक में अमेरिकी कॉलेज डीन केंद्रित हो गए हैं यानी डीन के पास अधिक ताकत एकत्रित हो गई है। वित्तीय स्थिति, फैकल्टी की नियुक्ति और उनका नियमितीकरण तथा उनको मिलने वाले वेतन भत्ते (और सालाना वेतनवृद्धि) आदि सभी ऐसे मामले हैं जिन पर डीन को अधिक नियंत्रण हासिल है। जो प्रोत्साहन अकादमिक प्रशासकों को दानदाताओं और राजनेताओं की मर्जी के मुताबिक का करने को प्रेरित करते हैं वही फैकल्टी पर नियंत्रण में भी मदद करते हैं। फैकल्टी के प्रतिष्ठित सदस्य ऐसे पदों पर हैं जो धनी दानदाताओं की बदौलत हैं, फिर चाहे वे कोई व्यक्ति हों या कंपनियां। शोध परियोजनाओं के लिए फंड और मोटे तौर पर कॉलेज या विश्वविद्यालय के भीतर शक्ति या प्रभाव के लिए यह आवश्यक है कि फैकल्टी प्रशासकों और दानदाताओं को खुश रखें।

अपने कॉलेज या विश्वविद्यालयों में और डीन तथा अध्यक्षों से निपटने के मामले में फैकल्टी को यह पता होता है कि कैसे मामले को दबाना है। ऐसा केवल अमेरिका में नहीं है। मैंने अकादमिक जगत में काफी वक्त बिताया है और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अकादमिक जगत की आंतरिक संस्कृति किसी कंपनी से एकदम अलग नहीं होती।

दुनिया के अन्य समझदार लोगों की तरह अकादमिक जगत के लोग भी जानते हैं कि कौन सी बात उनके लिए लाभदायक साबित होगी। वे समझते हैं कि प्रशासनिक लोगों और ताकतवर बाहर लॉबी को चिढ़ाना उनको महंगा पड़ सकता है।

चुनावों में सामान्य नैरेटिव क्यों होते हैं नाकाम

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए 2024 के चुनाव अभियान की एक बड़ी चुनौती यह है कि उसे विपक्षी दलों की ओर से प्रधानमंत्री पद का कोई ऐसा दावेदार नहीं मिल रहा है जिसके खिलाफ मोर्चा खोला जा सके। अगर ऐसा होता तब भाजपा को विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के दावेदार के खिलाफ जोरदार तरीके से मुहिम छेड़ने में काफी आसानी हो जाती।

वर्ष 2014 से ही भाजपा की लोक सभा की चुनावी रणनीति, एक व्यक्ति पर केंद्रित राष्ट्रपति शैली वाले प्रचार अभियान पर आधारित रही है। यह बेहद सामान्य रणनीति है लेकिन स्टार प्रचारक के होने का फायदा भी पार्टी को मिलता रहा है। हालांकि पार्टी के पक्ष में यह बात ज्यादा अच्छी होती अगर सामने विपक्ष का कोई कमजोर प्रधानमंत्री उम्मीदवार होता। ऐसे में इस उम्मीदवार को लक्षित करना और तुलनात्मक रूप से कमतर दिखाना भी सरल हो जाता। लेकिन इस चुनाव में ऐसा कोई एक व्यक्ति सामने नहीं हैं जिसे सत्ता पक्ष के मुख्य चेहरे के बरक्स खड़ा कर निशाना साधा जाए।

विपक्ष से जुड़े किसी ऐसे व्यक्ति के अभाव में सत्ता पक्ष के स्टार प्रचारक को मतदाताओं से स्थानीय मुद्दों पर बात करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है, जबकि क्षेत्रीय दल कई स्पष्ट और भावनात्मक तर्क पेश करने में सक्षम हैं।

विपक्ष थोड़ा बेहतर तरीके से ऐसे संगठित है कि कई क्षेत्रीय दल अपने गढ़ में अच्छी टक्कर देने के लिए तैयार हैं और कांग्रेस भी द्विपक्षीय गठबंधन में कनिष्ठ साझेदार बनने के लिए तैयार है। इसी वजह से भाजपा के स्टार प्रचारक को वास्तविक मुद्दों के बजाय अक्सर निजी हमले का सहारा लेना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर उन्होंने अपमानजनक लहजे में किसी एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए दावा किया कि मुख्यमंत्री को जिले के मुख्यालय का नाम नहीं पता है और दूसरी क्षेत्रीय पार्टी को 'फर्जी बच्चा' भी कह दिया।

आखिरी दो लोक सभा चुनावों के मुद्दे स्पष्ट और सामान्य थे जिसे भाजपा ने अच्छी तरह सोच-समझकर तैयार करते हुए पेश भी किया। वर्ष 2014 में इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया गया कि भाजपा के मुख्य उम्मीदवार ऐसे सुधारक हैं जो भ्रष्टाचार खत्म कर वृद्धि की रफ्तार बढ़ाएंगे। हकीकत चाहे जो भी हो लेकिन यह कथ्य (नैरेटिव) लोगों को बेहद भाया। वर्ष 2019 में भी 'देश की सुरक्षा करने वाले' जैसी बातें लोगों ने स्वीकार कीं। इसी वजह से भाजपा 'चुनावी लहर' में दो बार जीतने में सक्षम रही। पार्टी की वोट हिस्सेदारी में वर्ष 2009 (22 फीसदी) और 2019 (37 फीसदी) के बीच 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसकी सीटें भी 116 (वर्ष 2009) से बढ़कर 303 (वर्ष 2019) हो गईं।

वर्ष 2024 के चुनाव का सामान्य मुद्दा, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जुड़ा है और भाजपा इस स्थिति में नहीं है कि वह दावा कर सके कि उसके पास इसका कोई ठोस समाधान है क्योंकि पार्टी 10 साल से सत्ता में है और वह इन मुद्दों पर कोई सार्थक पहल करने में सक्षम नहीं हो पाई है।

भारत इतना विविधताओं और असमानताओं से भरा हुआ है कि इसे किसी सरल कथ्य या बयान से नहीं समझाया जा सकता। यहां दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। यहां की जलवायु तथा भौगोलिक दशाओं में भी काफी विविधता है। इसके अलावा आर्थिक और मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में भी बड़ा अंतर है।

तकनीकी तंत्र

देवांशु दत्ता

विविधता के मामले में इसकी केवल यूरोपीय संघ के साथ तुलना की जा सकती है जो एक महाद्वीप में फैले 27 अलग-अलग संप्रभु राष्ट्रों का समूह है। हालांकि यूरोपीय संघ भी भारत की तुलना में कम विविधता वाला है। वहां आर्थिक असमानता भी कम होने के साथ ही मानव विकास सूचकांक का दायरा भी कम है। असमानता मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर को आधार माना जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार (सबसे गरीब राज्य) की प्रति व्यक्ति आय लगभग 48,000 रुपये सालाना थी जबकि गोवा में यह सालाना लगभग 4.7 लाख रुपये थी जो देश के शीर्ष और सबसे निचले मानकों वाले राज्यों के बीच लगभग 10:1 के अंतर को दर्शाता है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति औसत आमदनी लगभग 1.48 लाख रुपये थी।

यूरोपीय संघ के देशों में बुल्गारिया सबसे गरीब है जिसकी प्रति व्यक्ति आय 16,900 डॉलर है वहीं लक्जमबर्ग सबसे अमीर है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय 1,31,380 डॉलर है। यूरोपीय संघ की औसत प्रति व्यक्ति आय 36,000 डॉलर है। पूरे यूरोपीय संघ में साक्षरता दर करीब शत-प्रतिशत है। भारत में 2017 के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के सर्वेक्षण में, केरल में सबसे अधिक 96 प्रतिशत साक्षरता दर दर्ज की गई थी और सबसे कम साक्षरता दर बिहार में 71 प्रतिशत थी।

इसी तरह जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर आदि में भी इतना ही बड़ा अंतर हैं। सिक्किम, नगालैंड, मिजोरम और केरल (प्रत्येक हजार में 5 से कम) में शिशु मृत्यु दर जर्मनी के बराबर है जबकि असम, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 40 से ऊपर है जो लगभग सूडान के समान स्तर पर है।

इसका मतलब है कि राष्ट्रीय स्तर पर सामान्य कथ्य के अनुरूप की गई नीतिगत पहल ज्यादा उपयोगी नहीं होती है। उदाहरण के लिए पूरे भारत में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए एक समान तरीके से बनाई गई योजना निश्चित रूप से बेतुकी होगी। कई मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं में भी इसी तरह के बेतुकेपन की झलक मिलती है।

चुनावी लहर सामान्य बयानों और कथ्यों से बनाई जा सकती है।

लेकिन भारत को सामान्य बयानों और कथ्यों के आधार पर काम करने वाली एक मजबूत केंद्र सरकार की आवश्यकता नहीं है। इसे राज्यों और क्षेत्रों में क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधित्व वाले एक ऐसे गठबंधन की आवश्यकता है जो असमानताओं का प्रबंधन प्रभावी ढंग से कर सके।

आपका पक्ष

चाबहार बंदरगाह समझौता बड़ी उपलब्धि

भारत ने चाबहार बंदरगाह का प्रबंधन 10 साल के लिए अपने हाथ में लेकर एक बड़ी समुद्री और व्यापारिक जीत हासिल की है। इसे इसकी पहली विदेशी परियोजना माना जा रहा है, जिससे अफगानिस्तान, ईरान और पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ उसके संबंधों में सुधार आने की संभावना है। वर्ष 2003 में चाबहार बंदरगाह के विकास पर भारत और ईरान के बीच सहमति बनने के बाद से पिछले कुछ वर्षों में बहुत कम प्रगति हुई थी। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बिगड़ते रिश्तों, बदलता वैश्विक परिदृश्य, हाल के इजरायल-हमास युद्ध के मद्देनजर उभरती हुई गलतियों ने भारत को ईरान के साथ अपने संबंधों को फिर से बनाने और व्यवस्थित करने के लिए मजबूर किया है। इस पृष्ठभूमि में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीसी) और ईरान के बंदरगाहों और समुद्री संगठन के बीच 10 वर्ष के लिए एक समझौता

भारत ने चाबहार बंदरगाह का प्रबंधन 10 साल के लिए अपने हाथ में लेकर एक बड़ी समुद्री और व्यापारिक जीत हासिल की

हुआ है। लिहाजा, चाबहार में टर्मिनल का परिचालन हमारे बुनियादी ढांचे और व्यापारिक क्षमताओं का दोहन करने के लिए महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह पारगमन समय को कम करने और माल ढुलाई लागत में अनुमानित 30 प्रतिशत की कटौती करने वाली वस्तुओं और सेवाओं का निर्बाध हस्तांतरण भी प्रदान करेगा। अमेरिका और पश्चिमी शक्तियों को चीन के साम्राज्यवादी मंसूबों का मुकाबला करने के लिए चाबहार बंदरगाह को एक सुरक्षा वाल्व के रूप में देखना चाहिए। उम्मीद है कि मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और हिंद महासागर के देशों के साथ भारत अपने संबंधों को मजबूत कर सकेगा। चाबहार परियोजना के ठोस आकार लेने के साथ, दक्षिण एशिया को मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ने के लिए रूस, ईरान तथा भारत के दिमाग की उपज, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ने प्रगति हासिल की है।

विजय सिंह अधिकारी, नैनीताल

रोजगार के साथ बेरोजगारी बढ़ाने में भी सहायक एआई

मशीनों को बुद्धिमान बनाकर इंसानों की तरह एआई से छात्रों को शिक्षा देने, ऑटोमेटेड कार्य होने से समय और खर्च की बचत के साथ ई-मेल फिल्टरिंग, ग्राहक सेवा कार्य जल्द और आसान करने से रोजगार में सहायक होगा। इस तरह एआई कमाई में तो वृद्धि करेगा। किंतु नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं होगा क्योंकि मानव का काम मशीनों द्वारा होने से बेरोजगारी का खतरा है।

बी एल शर्मा, उज्जैन

अकुशल पर संकट, कुशल के लिए अवसर

एआई एक दोधारी तलवार की तरह है। इससे कुशल लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर हो सकते हैं, वहीं अकुशल लोगों के लिए यह बेरोजगारी का कारण भी बनेगा। एआई क्षमता संपन्न रोबोट अनेक लोगों जैसे ड्राइवर, सफाईकर्मी, कस्टमर केयर आदि की नौकरी लेगा तो शिक्षक, प्रशिक्षक, चिकित्सा आदि नौकरियां इसके प्रभाव से बची रह सकती हैं। एआई के सकारात्मक उपयोग को सुनिश्चित करना और अधिकाधिक लोगों तक इसकी पहुंच तय करना रोजगार में दीर्घकालिक लाभदायक साबित होगा।

मोहित सोनी, कुक्षी

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

भारत की दीप्ति जीवनजी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर टी20 रेस में 55.07 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। पैरा एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता दीप्ति ने अमेरिका की ब्रियाना क्लार्क का 55.12 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा जो उसने पिछले साल पेरिस में बनाया था ।

मालीवाल प्रकरण

आरोप-प्रत्यारोप

मालीवाल पर हमले के मामले में केजरीवाल के सहायक की गिरफ्तारी के बाद 'आप' और भाजपा में आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष तथा 'आप' की राज्यसभा सांसद स्वाती मालीवाल पर कथित हमले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार नामजद हैं। यह मामला गंभीर होता जा रहा है। यह घटनाक्रम तिहाड़ जेल से केजरीवाल की वापसी के कुछ ही दिन के भीतर हुआ जहां उनको दिल्ली एक्साइज़ नीति निर्धारण में भ्रष्टाचार के आरोप में बंद किया गया था। अब कथित हमले में विभव कुमार की गिरफ्तारी से विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक दांवपेंचों की शुरुआत हो गई है। इस मामले में स्वाती मालीवाल केन्द्र में हैं जिन पर दिल्ली महिला आयोग-डीसीडब्लू में नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं के आरोप में 'एंटी-करप्शन ब्यूरो' जांच कर रहा है। पहले हमले की बात स्वीकारने वाली 'आप' अब आरोप लगा रही है कि मालीवाल को इस मामले में गिरफ्तारी की धमकी पर ब्लैकमेल किया गया था। विभव की गिरफ्तारी का संबंध इस जांच से है, जिसने पहले से ही अस्थिर स्थिति को और विस्फोटक बना दिया है। अपने सहायक की गिरफ्तारी के विरोध में अरविंद केजरीवाल ने 'आप' विधायकों, सांसदों और समर्थकों के साथ भाजपा मुख्यालय तक एक विरोध मार्च निकाल कर विभव के साथ एकजुटता प्रदर्शित की तथा भाजपा द्वारा राजनीतिक बदला लेने का 'खुलासा' किया। प्रधानमंत्री मोदी को भेजे एक वीडियो संदेश में केजरीवाल ने कहा है कि वे एक-एक कर गिरफ्तार करने के बजाय 'आप' के सभी नेताओं को एकसाथ गिरफ्तार कर लें। केजरीवाल ने जोर दिया कि विभव और मालीवाल के खिलाफ कार्रवाई 'आप' द्वारा भ्रष्टाचार का मुकाबला तथा प्रशासन में सुधार के प्रयासों को कुचलना है। दूसरी ओर भाजपा ने जोर दिया है कि भ्रष्टाचार-विरोधी कानून का पूरी सतर्कता से पालन किया जा रहा है। भाजपा नेताओं का तर्क है कि सार्वजनिक पदों पर पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जांच एक आवश्यक कदम है। मजेदार बात है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर खामोश रहने का निर्णय किया है। इस तटस्थ दृष्टिकोण का उद्देश्य 'आप' और भाजपा के बीच टकराव से दूर रहना है क्योंकि ये दोनों दिल्ली में उसके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं।

राजनीति में समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रकरण ऐसे समय हुआ है, जब दिल्ली में एक सप्ताह में 25 मई को मतदान है। इस बीच 'आप' और भाजपा के बीच टकराव विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच टकराव का अंग बन गया है। इस घटना के राजनीति पर दूरगामी परिणाम होंगे जिससे भावी चुनावों में मतदाताओं का दृष्टिकोण प्रभावित हो सकता है। फिलहाल मालीवाल पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है क्योंकि मामला अभी अदालत के विचाराधीन है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अतीत में दिए उनके कुछ बयान अजीब लगते हैं। एक बार उन्होंने ट्वीट किया कि वे 'सौभाग्यशाली बेटी' हैं, लेकिन दूसरे अवसर पर उन्होंने कहा कि बचपन में उनका यौन उत्पीड़न हुआ था। दोनों पार्टियों द्वारा एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप के बाद, दिल्ली की जनता पूरे प्रकरण पर गंभीर नजर रख रही है। उसे अनुमान है कि ऐसे समाधान निकलेंगे जिनसे 'राजनीतिक सुविधा' के बजाय सुशासन व न्याय को वरीयता मिलेगी। भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था, 'तीन चीजें-सूरज, चांद और सत्य लंबे समय तक छिपाई नहीं जा सकती हैं।' जल्द ही हमें पता चल जाएगा कि मालीवाल प्रकरण एक राजनीतिक षडयंत्र है अथवा यह 'आप' पार्टी सदस्यों पर हमले की रणनीति है।

अमेरिका-ईरान संबंध और भारत

भारत ने चाबहार बंदरगाह समझौते के माध्यम से ईरान के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की है। उसे अमेरिकन सरोकारों की पृष्ठभूमि में क्षेत्रीय हितों के साथ सावधानीपूर्वक संतुलन बनाना होगा।

भोपिंदर सिंह
(लेखक, सेवानिवृत्त सेनाधिकारी हैं)

भारत ने चाबहार बंदरगाह समझौते के माध्यम से ईरान के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की है। उसे अमेरिकन सरोकारों की पृष्ठभूमि में क्षेत्रीय हितों के साथ सावधानीपूर्वक संतुलन बनाना होगा। ईरान अनावश्यक रूप से अनेक अमेरिकन प्रशासनों की संवेदनशीलता का शिकार रहा है, हालांकि विभिन्न अमेरिकन सरकारों में ईरान से संबंधों के मामले में मतभेद भी रहे हैं। अमेरिका-ईरान संबंधों में टकराव की शुरुआत 1979 में हुई जब ईरानी क्रांति तथा इसके बाद अमेरिकन दूतावास में बंधकों के प्रकरण ने द्विपक्षीय संबंधों में भारी तनाव पैदा किया।

लेकिन अमेरिका से संबंधों को लेकर ईरान कम आहत नहीं है। ईरानियों को गहराई तक इस तथ्य ने झकझोर दिया था कि 1953 में उनके लोकप्रिय प्रधानमंत्री मुहम्मद मुसादेह के खिलाफ सैनिक-विद्रोह के पीछे अमेरिकन खुफिया एजेंसी सीआईए का हाथ था। निश्चित रूप से अयातुल्ला खुमैनी का 'धार्मिक शुद्धतावाद' अमेरिका से संबंध बिगाड़ने का एक और कारण बना। 'ईरानी इस्लामी क्रांति' के बाद खुमैनी ने वैचारिक रूप से 'पश्चिम'-विरोधी दृष्टिकोण अपनाया था। इसके साथ ही ईरानी जनता सद्दाम हुसेन को अमेरिकी-समर्थन भूली नहीं है जिनके कारण एक दशक तक ईरान-ईराक युद्ध चला था। हालांकि, बाद में अमेरिका ने स्वयं सद्दाम हुसेन को सत्ता से हटा दिया था, पर आज अमेरिकी सरकारें ईरान से संबंध खराब करने में अपनी इस भूमिका को सुविधाजनक रूप से भूल गई हैं। इसके बाद अमेरिकनों ने ईरान को 9-11 तथा अलकायदा-आईएसआईएल के जन्म से जोड़ दिया, हालांकि ईरान का इन दोनों घटनाओं से कोई संबंध नहीं था। वास्तव में सच्चाई यह है कि ईरान तथा उसके समर्थक बल सीरिया-ईराक क्षेत्र में आईएसआईएल से लगातार लड़ते रहे हैं। ईरान ने बड़ी सीमा तक अलकायदा को कमजोर करने में अपनी भूमिका निभाई थी, पर इसके बावजूद अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी।

अमेरिका के 'सहयोगी'-इज़राइल और अरब के शेखों की शतरंज में नस्ली टकराव का महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए उनको सीरिया, लेबेनान और यमन में ईरान की शक्तिशाली स्थिति पसंद नहीं है और अनुचित रूप से ईरान को लगातार 'शैतान की तरह' पेश किया जाता है। हालांकि, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देशों ने धार्मिक अतिवाद और आतंक फैलाने में ज्यादा बड़ी भूमिका अदा की है, पर उनको लगातार अमेरिकी सहायता मिल रही है जबकि ईरान पर विकलांगकारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिकनों ने एकपक्षीय रूप से ईरान नाभिकीय समझौता खारिज कर दिया, जबकि समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य पीप्लसवन देशों तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ की निगरानी एजेंसी 'इंटरनेशनल एटोमिक इनर्जी एजेंसी'-आईएईए ने पुष्टि की थी कि ईरान ने संधि की सभी शर्तों का पालन किया है। इज़राइल व अरब शेखों के दबाव में ईरान को लगातार मजबूर किया जा रहा है। उस पर मध्यपूर्व में होने वाली हर गलत चीज का ठीकरा फोड़ दिया जाता है, भले ही ईरान की इन घटनाओं में कोई भूमिका न रही हो।

'हमास' समूह का ईरान समर्थन करता है, जबकि अभी हाल तक सऊदी अरब व अन्य देश इसका समर्थन करते थे। इस बात के कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं हैं जो ईरान को 7 अक्टूबर, 2023 के हमले की योजना बनाने या उसके क्रियान्वयन से जोड़ सकें। लेकिन इसके बावजूद ईरान की संलिप्तता का शोर लगातार मचाया जा रहा है। किनारे धकेल देने पर मजबूरी में अपने संप्रभु गौरव को बनाए रखने के लिए ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। सीरिया में इज़राइलियों द्वारा उसके वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों को मारे जाने के बाद ईरान इसके लिए मजबूर हुआ है। ईरान के कथित षडयंत्रों को 'सिद्ध करने' के लिए बहु-प्रतीक्षित औचित्य की जरूरत थी और अमेरिका ने इसे दोनों हाथों से पकड़ा। अमेरिका में यह चुनाव वर्ष है और वह 'दुश्मन' ईरान के खिलाफ चुनावी लाभ के लिए कार्रवाई करते दिखना चाहता है। इससे स्थिति और खराब हुई है। पहले ईरान नाभिकीय समझौता बहाल करने के वादे पर सत्ता में आए जो बाइडेन अब डोनाल्ड ट्रंप को मुकाबले में पराजित करने के लिए अपना यह वादा भूल गए हैं। आज बाइडेन ईरानियों का 'मुकाबला करने' में डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वे ईरान पर और अधिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। व्हाइट हाउस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, 'सारी दुनिया ने देखा कि एक सप्ताह से भी कम समय पहले ईरान ने इज़राइल के खिलाफ अपनी एक सबसे बड़ी मिसाइल लांच की तथा उस पर ड्रोन विमानों से हमला किया। अपने सहयोगियों के साथ मिल कर संयुक्त राज्य अमेरिका ने इज़राइल की रक्षा की। हमने यह हमला विफल करने में सहायता की है। आज हम ईरान को इसके लिए जवाबदेह मान कर हम उसके खिलाफ नए प्रतिबंध तथा निर्यात नियंत्रण लगा रहे हैं।' इनका प्रतिबंधों और नियंत्रणों का प्रभाव अमेरिका से बहुत आगे तक जाता है। अमेरिका अब किसी ऐसे देश पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहा है जिसके ईरान से संबंध हों। इनमें संभवत: भारत भी है जिसने हाल ही में ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के प्रबंधन के 10 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पाकिस्तानी भू-मार्गों को छोड़ कर अफगानिस्तान और मध्य एशियाई गणतंत्रों तक पहुंच मार्ग देता है।

यह भारत को पाकिस्तान के दूसरी ओर महत्वपूर्ण सुविधा देता है तथा चीन द्वारा पाकिस्तान में विकसित ग्वादर बंदरगाह का जवाब है। इससे प्राचीन सभ्यता वाले देशों-भारत तथा ईरान के संबंध मजबूत होते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान अब पाकिस्तान से ऊब गए हैं, ऐसे में ईरान के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर कर नई दिल्ली ने इस क्षेत्र में चीन-पाकिस्तान धुरी का मुकाबला करने की बेहतरीन संभावनायें तैयार की हैं। जहां भारत को चीनी खतरों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका से संबंध बनाए रखने और मजबूत करने की जरूरत है, वहं उसे क्षेत्रीय सरोकारों को देखते हुए ईरान के मामले में अमेरिकी सरोकारों से स्वयं को अलग रखना होगा। यदि अमेरिका केवल अपने द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय दृष्टिकोण को महत्व दे तो भारत अमेरिका का 'अंध समर्थक' नहीं बना रह सकता है। यह भारत द्वारा निर्णय लेने में अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' बनाए रखने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भारत ने रूसी तेल खरीदने तथा मास्को के साथ नजदीकी संबंध बनाए रखने में इसी नीति का अनुसरण किया है, हालांकि इसके साथ ही उसने यूक्रेन की घटनाओं पर भी चिन्ता प्रकट की है।

वैसे अमेरिका ने भारतीय दृष्टिकोण और मजबूरियों को समझा है जो किसी प्रकार अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने को लक्षित नहीं थीं। वह केवल अपने हितों की ही रक्षा करना चाहती थीं। इसलिए भारत ने ऐसे मामलों में कोई बयानबाजी नहीं की। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए खासकर ईरान के मामलों में आक्रामक बयानतती से बाइडेन प्रशासन अपना ही नुकसान करेगा। इसलिए उसे चाबहार बंदरगाह के रखरखाव के दस वर्षीय समझौते के बारे में भारत और ईरान की मजबूरियों पर समग्र रूप से गौर करना चाहिए। अमेरिकी अधिकारी के बयान को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। ईरान से भारतीय समझौते के बारे में सवाल का जवाब मांगने पर उसने कहा, 'आपने कई बार अनेक मामलों में हमारा दृष्टिकोण देखा है। इसका अर्थ है कि ईरान से बिजनेस करने वाले किसी उद्यम को यह पता होना चाहिए कि वे स्वयं को प्रतिबंधों के संभावित खतरे के सामने रख रहे हैं।' वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अमेरिका अपने दृष्टिकोण पर बना रह सकता है, पर भारत को भी अपने हितों को देखते हुए काम करना होगा। भारत और अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में इस विरोधाभास को समझते और एक सीमा तक स्वीकार करते हैं। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि भारत के ईरान के साथ रणनीतिक समीकरणों का उद्देश्य अमेरिकी हितों को कमजोर करना नहीं है।

जटिल चुनौतियों से नीति परिवर्तन

आज की समस्याओं का समाधान केवल आध्यात्मिक हो सकता है और हमने युवा जनसंख्या को आध्यात्मिकता से वंचित रखा है। हमारी शिक्षा बहुत खतरनाक ढंग से जीवन विरोधी हो गई है।

आचार्य प्रशांत
(लेखक, वेदांत शिक्षक हैं)

भारत के महत्वपूर्ण मुद्दे स्थायी, परिवर्तनकारी परिवर्तन के लिए व्यावहारिक कार्रवाई और सामूहिक मानसिकता में बदलाव की मांग करते हैं। भारत को विभिन्न क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को समाज, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि से संबंधित मानना आकर्षक लगता है, लेकिन अनिवार्य रूप से सभी समस्याओं की जड़ें मनुष्य के दिमाग में होती हैं और स्वयं की पर्याप्त समझ की कमी से उत्पन्न होती हैं। इसलिए समाधान बाहरी और आंतरिक दोनों डोमेन में होने चाहिए। आइए भारत को परेशान करने वाले पांच प्रमुख संघर्षों और चुनौतियों पर नजर डालें। भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण में इन समस्याओं का रचनात्मक रूप से जवाब देना शामिल होगा।

यह सर्वविदित है कि जलवायु परिवर्तन एक मानवजनित घटना है। लद्दाख पहले से ही जलवायु परिवर्तन के कारण क्षेत्र की पारिस्थितिकी में होने वाले स्पष्ट बदलावों को लेकर आंदोलनरत है। यदि भारत ने तुरंत सुधारात्मक कदम नहीं उठाए तो पांच साल बहुत लंबा समय है। इस मुद्दे पर जन जागरूकता की भयावह कमी है जिसके कारण राजनीतिक निष्क्रियता हो रही है। हम देश को घेरने वाली भयानक गर्मी की लहरों से निपटने की योजना कैसे बना रहे हैं? फसल की घटती पैदावार और चरम मौसम की घटनाओं से गरीबों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हम नहीं जानते कि जिस जहरीली हवा का हम उपभोग कर रहे हैं या जिस जल संकट का हम सामना कर रहे हैं उसका स्रोत क्या है? हम वनों की कटाई और बड़े पैमाने पर कार्बन-उत्सर्जक बुनियादी ढांचे के निर्माण से हिमालय को बर्बाद करना जारी रख रहे हैं, यह जानते हुए भी कि इससे अनियमित बारिश के पैटर्न, ग्लेशियरों के पिघलने और अंतत: जीवन का विनाश हो रहा है, जैसा कि हम जानते हैं।

उपभोग के प्रति अंधी लालसा इस अंध विश्वास से आती है कि उपभोग किसी के जीवन की पूर्णता या सफलता का सूचक है। उपभोक्तावाद की इस धारणा के साथ हमारी आबादी का विशाल आकार आत्म-विनाश का नुस्खा है। अगले 5 वर्षों में, हमें मानव जाति के सामने मौजूद इस सबसे बड़े खतरे पर शिक्षा और जन-जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता है और साथ ही आत्म-जागरूकता पर कार्यक्रमों के माध्यम से उपभोग-आधारित दोषपूर्ण जीवन दर्शन को सही करने की दिशा में वास्तविक प्रयासों की भी आवश्यकता है। वही वासना जो ग्रह को नष्ट करने की धमकी देती है, पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के अधिकारों का भी हनन करती है। पशु अधिकारों के उल्लंघन, पारिस्थितिकी हानि और जैव विविधता विलुप्त होने की समस्याएँ - सभी एक ही स्रोत से उत्पन्न होती हैं। जब हम पशु अधिकारों की बात करते हैं, तो दुर्भाग्यवश आज यह जीवित रहने के बुनियादी अधिकार के लिए संघर्ष है। पिछले 50 वर्षों में ग्रह पर सभी जीवित प्रजातियों में से लगभग 50% विलुप्त हो गई हैं। इसका अधिकांश कारण हिंसक मानवीय कार्रवाई है। प्रतिदिन 100-1000 प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती हैं। साथ ही, यह प्राकृतिक विलुप्ति दर से 100 से 1000 गुना तेज है। भारतीय और मनुष्य के रूप में, हमने पूरे ग्रह के खिलाफ जिस तरह का कालीन प्रजातिनाशक लॉन्च किया है, उसके साथ हम शारीरिक या आध्यात्मिक रूप से जीवित रह सकते हैं। अपने पैमाने और क्रूरता में, यह पृथ्वी पर अब तक देखी गई किसी भी हिंसा की कार्रवाई से कहीं अधिक है।

यह देखना विशेष रूप से खेदजनक है कि भारत, अपनी अहिंसा के साथ, जीवन रूपों के प्रति अत्याचार के सबसे बुरे अपराधियों में से एक है। चाहे वह मांस निर्यात हो, डेयरी उद्योग का विस्तार हो, या तथाकथित विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से पशु आवासों का संगठित विनाश हो, यह सभी के लिए केवल विनाश का संकेत है। अगले 5 वर्षों में, मैं इस मोर्चे पर सीधी और मजबूत कार्रवाई देखना चाहता हूं, जो केवल सार्वजनिक चेतना की उत्तेजना के परिणामस्वरूप हो सकती है। वही वासना जो ग्रह को नष्ट करने की धमकी देती है, वह पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के अधिकारों का भी हनन करती है।. पशु अधिकारों के उल्लंघन, पारिस्थितिकी हानि और जैव विविधता विलुप्त होने की समस्याएँ - सभी एक ही स्रोत से उत्पन्न होती हैं। जब हम पशु अधिकारों की बात करते हैं, तो दुर्भाग्यवश आज यह जीवित रहने के बुनियादी अधिकार के लिए संघर्ष है। पिछले 50 वर्षों में ग्रह पर सभी जीवित प्रजातियों में से लगभग 50% विलुप्त हो गई हैं। इसका अधिकांश कारण हिंसक मानवीय कार्रवाई है। प्रतिदिन 100-1000 प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती हैं। साथ ही, यह प्राकृतिक विलुप्ति दर से 100 से 1000 गुना तेज है।

भारतीय और मनुष्य के रूप में, हमने पूरे ग्रह के खिलाफ जिस तरह का कालीन प्रजातिनाशक लॉन्च किया है, उसके साथ हम शारीरिक या आध्यात्मिक रूप से जीवित रह सकते हैं। अपने पैमाने और क्रूरता में, यह पृथ्वी पर अब तक देखी गई किसी भी हिंसा की कार्रवाई से कहीं अधिक है। यह देखना विशेष रूप से खेदजनक है कि भारत, अपनी अहिंसा के साथ, जीवन रूपों के प्रति अत्याचार के सबसे बुरे अपराधियों में से एक है। चाहे वह मांस निर्यात हो, डेयरी उद्योग का विस्तार हो, या तथाकथित विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से पशु आवासों का संगठित विनाश हो, यह सभी के लिए केवल विनाश का संकेत है।

अगले 5 वर्षों में, मैं इस मोर्चे पर सीधी और मजबूत कार्रवाई देखना चाहता हूं, जो केवल सार्वजनिक चेतना की जागृति के परिणामस्वरूप हो सकती है। भारत की शिक्षा की स्थिति पर सार्वजनिक आँकड़े दर्शाते हैं कि देश कितने गहरे संकट में है। स्कूली छात्रों की बुनियादी मात्रात्मक और भाषाई क्षमताओं पर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, कॉलेज उत्तीर्ण छात्रों की बेरोजगारी का तो जिक्र ही नहीं किया गया है। विकसित दुनिया और विकासशील देशों की तुलना में, यह भारतीय समाज में शिक्षा को महत्व न देने की बात को उजागर करता है। आज की समस्याओं का समाधान केवल आध्यात्मिक हो सकता है और हमने युवा आबादी को आध्यात्मिकता से वंचित रखा है। हमारी शिक्षा बहुत खतरनाक ढंग से जीवन विरोधी हो गई है। मनुष्य तभी जीवित है जब वह सोच सके और समझ सके।

आप की बात

मोदी की लहर

लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान समाप्त होने के बाद अब 25 मई और 1 जून को बाकी दो चरणों के चुनाव के बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे का सबको बेसब्री से इंतजार है। वैसे चुनाव परिणाम के संकेत शेयर बाजार से मिलने लगे हैं। पूंजी बाजार अत्यंत डरपोक होता है और किसी भी अफ्वाह पर वह तुरंत अपनी प्रतिक्रिया बता देता है। इस चुनाव में जो लोग परास्त होने जा रहे हैं उन्हें कोई लहर नजर नहीं आ रही है, जबकि कुछ राज्यों को छोड़कर देशभर में मोदी की लहर हिलोरें मार रही है। भाजपा तथा उसके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन भी इस बार चुनाव में भरपूर मेहनत कर रहा है। भाजपा और एनडीए योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से चुनाव अभियान चला रहा है। जहां तक शेयर बाजार और अवैध रूप से चलने वाले सट्टा बाजार का सवाल है, तीसरे राउंड के बाद जो शेयर बाजार धड़ाम से गिर पड़ा था, वही अब 4 जून के परिणाम के बाद नई ऊंचाईयां छूकर बतायेगा। सटोरियो ने भाजपा को 300 से 335 सीटें तक मिलने का अनुमान लगाया है। मतदान केन्द्रों पर खासकर मध्य वर्ग व निम्न मध्य वर्ग जिस उत्साह के साथ मतदान कर रहा है, उससे भाजपा नेताओं का यह अनुमान सही सिद्ध हो सकता है कि देश में सत्ता-समर्थक लहर है।

-सुभाष बुडावन वाला, रतलाम

राम मंदिर पर राजनीति

सदियों से लंबित प्रकरण सुलझ कर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। अब सैकड़ों-हजारों सालों तक भगवान श्रीराम का आशीर्वाद भक्तों पर बना रहेगा। विशुद्ध राजनीतिक इच्छाशक्ति व सनातन धर्म के प्रति आस्था व उसके आधार पर संघर्ष के चलते आज भगवान् राम टेंट से निकल कर विशाल मंदिर में विराजमान हो गए हैं। हालांकि, बहुत से राजनेताओं व राजनीतिक दलों को भव्य राम मंदिर का निर्माण पसंद नहीं आया है, लेकिन अब कोई भी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल फिर रामलला को मंदिर से टेंट में लाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उनका यह दावा भी निरर्थक है कि अगर सत्ता में होते तो हम भी राम मंदिर का निर्माण करते। जनता उनकी कथनी और करनी से अच्छी तरह परिचित है। सारी जनता का विश्वास है कि यदि केन्द्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार न होती तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इसे लटकाने का भरपूर प्रयास किया जाता। जनता को अवसरवादी राजनेताओं से पूछना चाहिए कि देश के अन्य हजारों मंदिरों के बारे में उनका क्या विचार है जिनको तोड़ कर मस्जिदें बना ली गई थीं। भारत की अधिकांश हिंदू जनता अब जाग गई है और उसे भ्रमित करना असंभव है।

- शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

जमानत का प्राविधान

जमानत का प्राविधान लंबे समय से विवादास्पद रहा है। व्यापक भ्रष्टाचार, बेईमानी और अनैतिक कृत्यों के चलते अदालतें और जेलें हमेशा व्यस्त रहती हैं। अधिकांश आरोपी जनसेवकों के लिए जमानत मिलना मानो एक सामान्य बात हो गई है। वे जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी अपने अधूरे सपनों को पूरा करने की योजना बनाते रहते हैं। अदालतें जमानत देकर एक तरह से उन्हें और आज़ादी प्रदान दे देती हैं। विडंबना है कि अदालतें जिन अपराधियों को सजा देती हैं, उनमें से अनेक जमानत पर बाहर आकर फिर से वही या उससे भी भयानक अपराध करते हैं। यह दुष्चक्र कभी समाप्त नहीं होता। अदालतों में तारीखें पड़ती रहती हैं और जमानत पर रिहा आरोपी अपने काम-धंधे निपटाते रहते हैं। यह सब देखकर आम जनता के मन में निराशा और हताशा पैदा होती है। आम आदमी सोचता है कि जो लोग बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वे जमानत पर छूट जाएंगे और अपनी गतिविधियों को जारी रखेंगे। इसे देखते हुए न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। जमानत की शर्तें सख्त होनी चाहिए ताकि जो लोग समाज को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें आसानी से छूट न मिले। न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेज़ी लाने की आवश्यकता है।

अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़

महिला उत्पीड़न

देश की राजधानी में मुख्यमंत्री के आवास पर एक राज्यसभा सांसद के साथ बदसलूकी का मामला सामने आने पर आम आदमी पार्टी-आप की लीपापोती अत्यधिक चिन्ता का विषय है। पुलिस विभाग को निष्पक्ष एवम त्वरित कार्रवाई कर दोषी को कठोरतम सजा दिलानी चाहिए। चिन्ता की बात है कि राजनीतिक दल महिला उत्पीड़न के मामलों में भी अपनी दलगत राजनीति अपनाने से बाज नहीं आते हैं। राजनीतिक दलों को यह प्रवृत्ति बदलना होगी ताकि महिला अस्मिता व महिला उत्पीड़न के सवाल पर सारा देश एक साथ खड़ा हो सके और महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। मालीवाल प्रकरण में यह भी चिन्ता की बात है कि केजरीवाल ने आरोपी को बचाने का न केवल भरपूर प्रयास किया, बल्कि इसके लिए एक और महिला मंत्री को आगे कर दिया है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री भी संदेशखाली में महिला उत्पीड़न को संकुचित राजनीतिक व चुनावी राजनीति के दृष्टिकोण से देख रही हैं। महिला उत्पीड़न में कुछ महिलाओं की प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका चिन्ता का विषय है।

- वीरेन्द्र कुमार जाटव, दिल्ली

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।